सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 152, नई दिल्ली, रविवार 10 अगस्त 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जब तक जीना, तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

03 जलेबी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है : संजय बाटला

06 वैज्ञानिक सुधार के 78 सालः स्वतंत्रता के बाद से विज्ञान

08 सिंहभूम में सीआरपीएफ के दो जवान पुनः घायल ,एयर लिफ्ट कर रांची भेजा

पुराने वाहनों के नाम पर बैन और अपने प्रिय बाहरी राज्यों में पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को पद के बल का दुरूपयोग कर जनता के वाहन जबरदस्ती उठवाकर देना दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम

कौन कौन है इसका हिस्सेदार , बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। हमने आपको 8 अगस्त 2025 के अंक में सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी निर्देश कि कापी के साथ जानकारी उपलब्ध करवाई थीं की भारत देश में अलग अलग राज्यों से वाहन स्क्रैप डीलरो को प्राप्त मान्यता में से अनगिनत पंजीकृत वाहन स्क्रैप डीलरो को नीलामी द्वारा स्क्रैप के वाहन खरीदने पर सड़क परिवहन एवम्-राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूरी तरह की रोक लगा दी गई है। **इसके पीछे जो कारण स्पष्ट रूप से सामने आए है वह सिद्ध करते हैं की वाहन स्क्रैप डीलरो ने परिवहन विभाग के आला अधिकारियों के साथ मिलकर जनता के साथ बड़ी लूट की है।**

यहां आपकी जानकारी के लिए एक बात और स्पष्ट कर दू वाहन स्क्रैप डीलरो ने लुट सिर्फ जनता के साथ ही नहीं की अपितु राज्य सरकारों और भारत सरकार के राजस्व से भी बहुत बड़ी लूटमार की है और यह सब उन्होंने किया है राज्यों के परिवहन विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभक्त से।

आपकी जानकारी के लिए बता दूं **लूटमार करवाने में नंबर वन पर जो राज्य परिवहन विभाग** है उसका नाम है दिल्ली परिवहन विभाग जी हां पूरे देश में जितनी लूटमार हुई है उसका 50% से अधिक की लूट करवाने में भूमिका निभाने का श्रेय सिर्फ दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारियों का है।

सबसे बड़ी सोचने योग्य बात यह है की इस स्कैम और सरकारी राजस्व से लूटमारी की पूरी जानकारी भारत सरकार के गृह मंत्री, गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल दिल्ली, मुख्य सचिव दिल्ली, दिल्ली सरकार, सीबीआई, पुलिस कमिश्नर दिल्ली पुलिस, एंटीकरप्शन विभाग, विजीलेंस विभाग, तक को है उसके बावजूद किसी के भी द्वारा सरकारी राजस्व की लूट, जनता से लूट के साथ जनता की सुरक्षा में सेंध जैसा गंभीर मामला होने के बावजूद इसमें लिप्त अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही तक करने की कोशिश नहीं की ?

इस लूटमार की कीमत आंकी जाएगी तो यह अरबों रुपए में है क्या इसीलिए सब कुछ जानते हुए भी सब चुप है और कार्यवाही करने से पीछे हट रहे है ?

क्या जनता की सुरक्षा में सेंध,

सरकारी राजस्व में लुट,

जनता से लूट,

और सरकारी पद की ताकत का दुरूपयोग कानून की दृष्टी में सजा के पात्र नहीं हैं ?

अगर भारत सरकार, गृह मंत्रालय, उपराज्यपाल दिल्ली, दिल्ली सरकार इस गंभीर मुद्दे और स्कैम पर चुप्पी साधे बैठे हैं तो भारत देश की उच्चतम न्यायालय को इस पर तत्काल संज्ञान लेना नहीं बनता आखिर वो भी चुप क्यों ?

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) 'उफ्तत्सा' द्वारा जीएसटी नियमावली, इनपुट घोटाला और भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व आंदोलन

स्थान: राष्ट्रीय स्तर, विशेष रूप से राउरकेला (ओड़िशा), मुंगेर (बिहार), सिरसा, कुलां,कैथल,जींद,और हिसार व अन्य (हरियाणा),भिलाई, रायपूर (छत्तीसगढ़) और हनुमानगढ़ (राजस्थान)
विषय: त्रिस्तरीय जीएसटी के नकारात्मक प्रभाव और परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार के खिलाफ सिंगल मोटर मालिकों का आंदोलन

परिवहन विशेष न्यूज

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) उफ्तत्सा (United Front for Transport and Sarthi Associations- UFTTSA) ने सिंगल मोटर मालिकों और परिवहन क्षेत्र के हितधारकों के हक में त्रिस्तरीय जीएसटी (CGST, SGST, IGST) प्रणाली के दुष्प्रभावों और चेक पोस्टों पर हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन और विरोध प्रदर्शन जारी है व संघर्ष लगातार जारी रखने की बात की है। यह प्रेस नोट इन्हीं संदर्भ है और जड़ति समस्याओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करता है।

त्रिस्तरीय जीएसटी का सिंगल मोटर मालिकों पर प्रभाव

भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू जीएसटी ने परिवहन क्षेत्र, विशेष रूप से सिंगल मोटर मालिकों (जो एक या कुछ ट्रकों के मालिक हैं और छोटे पैमाने पर परिवहन व्यवसाय चलाते हैं) पर गहरा प्रभाव डाला है। निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ सामने आई हैं:

जटिल अनुपालन और लागत : जीएसटी के तहत मासिक/तिमाही रिटर्न (GSTR-1, GSTR-3B) और ई-वे बिल जनरेट करने की अनिवार्यता ने सिंगल मोटर मालिकों पर आर्थिक और तकनीकी बोझ बढ़ाया है। अधिकांश मालिक डिजिटल साक्षर नहीं हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पर निर्भर रहते हैं, जिससे उनकी मासिक लागत 2,000-5,000 रुपये तक अतिरिक्त बोझ अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है।

उच्च कर दरें: परिवहन सेवाओं पर 12-18-28% जीएसटी दर लागू होती है, जो कम लाभ मार्जिन पर काम करने वाले मोटर मालिकों के लिए बोझिल है। ईंधन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) उपलब्ध न होने और पुराने वाहनों की बिक्री पर 18% जीएसटी ने उनकी आर्थिक स्थिति को और भी कमजोर किया है।

बड़े कॉरपोरेट्स व व्यवसाईयों का दबदबा : ई-कॉमर्स और बड़ी लॉजिस्टिक्स कंपनियाँ (जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट, डिलीवरी) कम भाड़ा दरें थोपती हैं, जिससे सिंगल मोटर मालिक प्रतिस्पर्धा में लगातार पिछड़ रहे हैं। जीएसटी अनुपालन के लिए बड़े कॉरपोरेट्स के पास संसाधन हैं जिससे व इनपुट का लाभ लगातार लेते हुए छोटे मालिकों के लिए अकाट्य प्रतिस्पर्धा ख़डी कर रहे हैं,क्योंकि छोटे गाड़ी मालिकों के पास इनपुट लेने की राह असम्भव सी है1

आर्थिक संकट: जीएसटी की लागत, उच्च ईंधन और टोल शुल्क (10,000-20,000 रुपये प्रति अंतर-राज्यीय यात्रा), और कम मांग के कारण कई मोटर मालिक कर्ज में डूब गए हैं, उनकी गाड़ियां या तो वित्तीय कम्पनीयों द्वारा खिंच ली गयी हैं या वे व्यवसाय बंद करने को मजबूर हुए हैं।

भ्रष्टाचार का मुद्दा : परिवहन क्षेत्र में भ्रष्टाचार सिंगल मोटर मालिकों के लिए एक गंभीर समस्या है।

प्रमुख बिंदु:

चेक पोस्टों पर अनुचित वसूली: जीएसटी और परिवहन नियमों के नाम पर फर्जी तरीके से परिवहन विभाग व पुलिस द्वारा चेक पोस्टों पर मोटर मालिकों से 1,200-3,000 रुपये प्रतिदिन की अवैध वसूली की जा रही है। गलत या अधूरे ई-वे बिल के लिए 20,000-3,00,000 रुपये या उससे अधिक तक का दंड लगाया जाता है। देश में कई ढाबों व पेट्रोल पम्प पर जीएसटी विभाग द्वारा जब्त गाड़ियां महिनो से ख़डी हैं-वैसे सरकारी गंत्वयों के बजाय गैर सरकारी स्थानों पर जब्त ख़डी गाड़ियों का खड़ा होना कई सवाल उत्पन्न करता है1

मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़, पश्चिमबंगाल में विशेष भ्रष्टाचार: राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने मध्य प्रदेश जीएसटी विभाग पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें छोटे मालिकों को रिश्वत के लिए बिच सड़क परेशान किया जाता है।पश्चिम बंगाल में डंडा टैक्स व मेकेनिकल एंव अन्य वसुली मोटर मालिकों के गले का फांस बन चूका है1

उफ्तत्सा द्वारा विरोध प्रदर्शन और आंदोलन

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) उफ्तत्सा ने सिंगल मोटर मालिकों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए देशभर में कई विरोध प्रदर्शन और आंदोलन लगातार आयोजित किए हैं।

प्रमुख मांगें –

परिवहन संबंधित जीएसटी दरों को सीधे 5% तक किया जाए एवं इसका सरलीकरण कर, सिंगल विंडो सिस्टम के तहत सीधे मोटर मालिक द्वारा भरे जाने के लायक फॉर्मेट तैयार कर कार्यकारी किया जाये1

वर्षों से लंबीत जीएसटी काउंसिल का शीघ्रता शीघ्र सभी राज्यों में गठन कर कार्यकारी किया जाए 1

मोटर मालिकों पर जीएसटी के अंतर्गत सभी लंबित मामलों को माफ़ी योजना के तहत 10% जुर्माने के तहत तुरंत रद्द किया जाए1

गैर सरकारी स्थान व निजी गोदाम में खड़े व जीएसटी द्वारा जब्त किए गए वाहनों को तुरंत रिहा करते हुए संलग्न अधिकारियों को जांच के दायरे में लिया जाए1

नेतृत्व: राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव,जरनेल सिँह,मंजीत सिँह,हरदीप वढेरा, राधेश्याम मल्लिक, अजय सिंगला,रविंद्र बधानी, नरेश गोछी, बलजीन्द्र सहारन,होशियार सिँह, रामफल जी, मलकित सिँह, राकेश अग्रवाल, मोहम्मद अफ़सर,ब्रजेश जेसवाल, शिवराज यादव, प्रभात शाह,सतकुँवार गर्ग, महेंद्र सिँह, रणवीर सिँह जैसे अन्य सैकड़ों संग्रामी नेताओं व हजारों बंधुओं ने मोटर मालिकों व ट्रांसपोर्टरों एंव सारथी बंधुओं को संगठित होने का सफलतापूर्वक आह्वान किया1

प्रभाव: इस आंदोलन ने बिहार, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओड़िशा, झारखण्ड, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, पंजाब,छतीसगढ़, मध्यप्रदेश ही नहीं अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र में सिंगल मोटर मालिकों को एकजुट करने और उनकी मांगों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका सार्थकता पूर्ण निभाई।

मुख्य गतिविधियाँ:

जागरूकता अभियान, सभाएं और प्रदर्शन।

मांग पत्रों के माध्यम से सरकार पर दबाव।

प्रभाव: इस अभियान ने चेकिंग प्रक्रिया में सुधार के लिए कुछ क्षेत्रों में सरकारी ध्यान आकर्षित किया, विभिन्न राज्यों में चालान माफ़ी,राजकीय टोल का निरस्तरीकरण, सेकड़ों की संख्या में पार्किंग व्यवस्था, परिवहन आयोग पर विधिवत विचार के अलावा मुख्य रूप से पुरे राष्ट्र में सिंगल मोटर मालिक, ट्रांसपोर्टर्स व सारथी बंधुओं की सशक्त आवाज बनने में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की1

भविष्य की रणनीति :

उफ्तत्सा ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार इन मांगों को जल्द पूरा नहीं करती, तो सिंगल मोटर मालिकों और परिवहन कर्मियों के साथ मिलकर देशव्यापी आंदोलन तेज किया जाएगा। संगठन ने ट्रक मालिकों से एकजुट होकर आगामी सभी चुनावो में अपनी मांगों को राजनीतिक दबाव के रूप में उपयोग करने का भी आह्वान किया है।

संपर्क: राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) उफ्तत्सा

अध्यक्षः डॉ. राजकुमार यादव

प्रकाशकः उफ्तत्सा मीडिया सेल

नोटः इस प्रेस नोट में दी गई जानकारी हाल की गतिविधियों और संगठन के बयानों पर आधारित है।

झारखंड के चांडिल स्टेशन पर दो मालगाड़ी एक्सीडेंट, दर्जनों डिब्बे वे पटरी, 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

सरायकेला। द पू रेल के सरायकेला खरसावां जिला अन्तर्गत चांडिल स्टेशन पर दो मालगाड़ी की आपस में टक्कर हुई है, जिसकी वजह से 20 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं. ये हादसा शुक्रवार देर रात चांडिल स्टेशन पर हुआ. इस दुर्घटना की वजह से इस रूट पर आने-जाने वाले यात्रियों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. घटना की बात करें तो पुरुलिया-चांडिल सेक्शन पर पहले एक मालगाड़ी के 10 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतर गए थे, तभी दूसरी तरफ से आने वाली मालगाड़ी के डिब्बे इन उतरे डिब्बों से टकरा गए.

दो मालगाड़ियों के एक साथ पटरी से उतर जाने से ट्रेन सेवाएं पूरी तरह ठप हो गईं. खबर के अनुसार अभी तक 20 से ज्यादा यात्री ट्रेनें रद्द की जा चुकी हैं. हादसे की सूचना मिलते ही वरिष्ठ रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे और पटरी से उतरे डिब्बों को हटाने का काम शुरू हो गया.

इस घटना के कारण रांची-हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें रद्द कर दी गईं, जबकि कुछ अन्य को वैकल्पिक मार्गों से चलाया जा रहा है. अच्छी खबर ये है कि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है. हालांकि रक्षाबंधन होने की वजह से कई यात्रियों को अपने गंतव्य पहुंचने में समय लग रहा है.

पुरुलिया और आद्रा जैसे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई. वहीं अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि सामान्य ट्रेन सेवाएं कब शुरू होंगी, जिससे यात्री रक्षाबंधन के दिन अपने गंतव्य तक पहुंच सकें. हालांकि खबर है स्थिति सामान्य होने में 24 घंटे का समय लग सकता है।

चार-युग और उनकी विशेषताएं

'युग' शब्द का अर्थ होता है एक निर्धारित संख्या के वर्षों की काल-अवधि। जैसे सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग, कलियुग आदि ।

यहाँ हम चारों युगों का वर्णन करेंगें। युग वर्णन से तात्पर्य है कि उस युग में किस प्रकार से व्यक्ति का जीवन, आयु, ऊँचाई, एवं उनमें होने वाले अवतारों के बारे में विस्तार से परिचय देना। प्रत्येक युग के वर्ष प्रमाण और उनकी विस्तृत जानकारी कुछ इस तरह है -

सत्ययुग

यह प्रथम युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है -

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 17,28,000 वर्ष होती है ।

इस युग में मनुष्य की आयु – 1,00,000 वर्ष होती है ।

मनुष्य की लम्बाई – 32 फिट (लगभग) [21 हाथ]

सत्ययुग का तीर्थ – पुष्कर है ।

इस युग में पाप की मात्र – 0 विश्वा अर्थात (0%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 20 विश्वा अर्थात (100%) होती है ।

इस युग के अवतार – मत्स्य, कूर्म, वाराह, नृसिंह (सभी अमानवीय अवतार हुए) है ।

अवतार होने का कारण – शंखासुर का वध एंव वेदों का उद्धार, पृथ्वी का भार हरण, हरिण्याक्ष दैत्य का वध, हिरण्यकश्यपु का वध एवं प्रह्लाद को सुख देने के लिए।

इस युग की मुद्रा – रत्नमय है ।

इस युग के पात्र – स्वर्ण के है ।

त्रेतायुग

यह द्वितीय युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है –

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 12,96,000 वर्ष होती है ।

इस युग में मनुष्य की आयु – 10,000 वर्ष होती है ।

मनुष्य की लम्बाई – 21 फिट (लगभग) [14 हाथ]

त्रेतायुग का तीर्थ – नैमिषारण्य है ।

इस युग में पाप की मात्रा – 5 विश्वा अर्थात (25%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 15 विश्वा अर्थात (75%) होती है ।

इस युग के अवतार – वामन, परशुराम, राम (राजा दशरथ के घर)

अवतार होने के कारण – बलि का उद्धार कर पाताल भेजा, मदान्ध क्षत्रियों का संहार, रावण-वध एवं देवों को बन्धनमुक्त करने के लिए ।

इस युग की मुद्रा – स्वर्ण है ।

इस युग के पात्र – चाँदी के है ।

.द्वापरयुग

यह तृतीय युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है –

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 8.64,000 वर्ष होती है ।

इस युग में मनुष्य की आयु - 1,000 होती है ।

मनुष्य लम्बाई – 11 फिट (लगभग) [7 हाथ]

द्वापरयुग का तीर्थ – कुरुक्षेत्र है ।

इस युग में पाप की मात्रा – 10 विश्वा अर्थात (50%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 10 विश्वा अर्थात (50%) होती है ।

इस युग के अवतार – कृष्ण, (देवकी के गर्भ से एंव नंद के घर पालन-पोषण), बुद्ध (राजा के घर)।

अवतार होने के कारण – कंसादि दुष्टो का संहार एंव गोपों की भलाई, दैत्यो को मोहित करने के लिए ।

इस युग की मुद्रा – चाँदी है ।

इस युग के पात्र – ताम्र के हैं ।

.कलियुग

यह चतुर्थ युग है इस युग की विशेषताएं इस प्रकार है –

इस युग की पूर्ण आयु अर्थात कालावधि – 4,32,000 वर्ष होती है ।

इस युग में मनुष्य की आयु – 100 वर्ष होती है ।

मनुष्य की लम्बाई – 5.5 फिट (लगभग) [3.5 हाथ]

कलियुग का तीर्थ – गंगा है ।

इस युग में पाप की मात्रा – 15 विश्वा अर्थात (75%) होती है ।

इस युग में पुण्य की मात्रा – 5 विश्वा अर्थात (25%) होती है ।

इस युग के अवतार – कल्कि (ब्राह्मण विष्णु यश के घर) ।

अवतार होने के कारण – मनुष्य जाति के उद्धार अधर्मियों का विनाश एंव धर्म कि रक्षा के लिए।

इस युग की मुद्रा – लोहा है।

इस युग के पात्र – मिट्टी के है।

विश्व शेर दिवस आज

हर साल 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है ताकि इस राजसी और साहसी जानवर के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके और उनकी सुरक्षा एवं संवर्धन हेतु समर्थन जुटाया जा सके। पिछले सौ वर्षों में, दुनिया भर में शेरों की संख्या में लगभग 80% की गिरावट देखी गई है। बड़ी बिल्लियों की इस प्रजाति के संरक्षण और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से कुछ साल पहले इस दिन की शुरुआत की गई थी।

शेरों का महत्व और यह दिन

==========

वर्ल्ड वाइड फंड (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ) के अनुसार , शेर कभी अफ्रीका, एशिया और यूरोप में पाए जाते थे, लेकिन इन महाद्वीपों में पिछले कुछ वर्षों में उनकी संख्या में काफी गिरावट आई है।

साहस, क्रूरता और शक्ति का प्रतीक ये राजसी बिल्लियाँ व्यापक आवास हानि के कारण खतरे में हैं

इस प्रकार, उनकी और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए संबंधित समुदायों और अन्य संगठनों द्वारा उपाय किए जा रहे हैं

जहां तक भारत का सवाल है, यह राजसी एशियाई शेर का घर है , जो सासन-गिर राष्ट्रीय उद्यान के संरक्षित क्षेत्र में निवास करता है।

भारत में शेरों की स्थिति और संरक्षण पहल

==========

भारत राजसी एशियाई शेरों का घर है, और उनका संरक्षित निवास स्थान गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान है। एशियाई शेर पुनःप्रवेश परियोजना भारत सरकार द्वारा एशियाई शेरों की शेष आबादी को देश के अन्य भागों में पुनःप्रवेश के माध्यम से स्थानांतरित करके संरक्षित करने के लिए शुरू की गई थी।

15 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रोजेक्ट लायन के तहत कुनो-पालपुर वन्यजीव अभयारण्य के अलावा छह नए स्थलों की पहचान की गई है। यह कार्यक्रम एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए शुरू किया गया है, जिनकी अंतिम शेष जंगली आबादी गुजरात के एशियाई शेर परिदृश्य में है।

भविष्य में शेरों के संभावित पुनर्वास के लिए पहचाने गए छह नए स्थल निम्नलिखित हैं:

माधव राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश
सीतामाता वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, राजस्थान
गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, मध्य प्रदेश
कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान
जेसोर-बलराम अंबाजी डब्ल्यूएलएस और आसपास का परिदृश्य, गुजरात

चक्रवर्ती सम्राट राम बारह कला और श्री कृष्ण सोलह कलाओ के थे ज्ञाता ! जानिये कलाओ के रहस्य !

राम 12 कलाओं के ज्ञाता थे तो श्रीकृष्ण सभी 16 कलाओं के ज्ञाता हैं। चंद्रमा की सोलह कलाएं होती हैं। सोलह श्रृंगार के बारे में भी आपने सुना होगा। आखिर ये 16 कलाएं क्या है? उपनिषदों अनुसार 16 कलाओं से युक्त व्यक्ति ईश्वरतुल्य होता है।आपने सुना होगाकुमति, सुमति, विक्षित, मूढ़, क्षित, मूर्च्छित, जाग्रत, चैतन्य, अचेत आदि ऐसे शब्दों को जिनका संबंध हमारे मन और मस्तिष्क से होता है, जो व्यक्ति मन और मस्तिष्क से अलग रहकर बोध करने लगता है वहीं 16 कलाओं में गति कर सकता है।

*चन्द्रमा की सोलह कला :अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शाशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इसी को प्रतिपदा, दूज, एकादशी, पूर्णिमा आदि भी कहा जाता है।

उक्तरोक्त चंद्रमा के प्रकाश की 16 अवस्थाएं हैं उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है। जिसकी अवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की इन सोलह अवस्थाओं से 16 कला का चलन हुआ। व्यक्ति का देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है।

*मनुष्य (मन) की तीन अवस्थाएं :प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तीन अवस्थाओं का ही बोध होता है:- जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति। क्या आप इन तीन अवस्थाओं के अलावा कोई चौथी अवस्था जानते हैं? जगत तीन स्तरों वाला है- 1.एक स्थूल जगत, जिसकी अनुभूति जाग्रत अवस्था में होती है। 2.दूसरा सूक्ष्म जगत, जिसका स्वप्न में अनुभव करते हैं और 3.तीसरा कारण जगत, जिसकी अनुभूति सुषुप्ति में होती है।

तीन अवस्थाओं से आगे: सोलह कलाओं का अर्थ संपूर्ण बोधपूर्ण ज्ञान से है। मनुष्य ने स्वयं को तीन अवस्थाओं से आगे कुछ नहीं जाना और न समझा। प्रत्येक मनुष्य में ये 16 कलाएं सुप्त अवस्था में होती है। अर्थात इसका संबंध अनुभूत यथार्थ ज्ञान की सोलह अवस्थाओं से है। इन सोलह कलाओं के नाम अलग-अलग ग्रंथों में भिन्न-भिन्न मिलते हैं।

इन सोलह कलाओं के नाम अलग-अलग ग्रंथों में अलगे अलग मिलते हैं।

*1.अन्नमया, 2.प्राणमया, 3.मनोमया, 4.विज्ञानमया, 5.आनंदमया, 6.अतिशयिनी, 7.विपरिनाभिमी, 8.संक्रमिनी, 9.प्रभवि, 10.कुंथिनी, 11.विकासिनी, 12.मर्यदिनी, 13.सन्हालादिनी, 14.आह्लादिनी, 15.परिपूर्ण और 16.स्वरुपवस्थित।

*अन्यत्र 1.श्री, 3.भू, 4.कीर्ति, 5.इला, 5.लीला, 7.कांति, 8.विद्या, 9.विमला, 10.उत्कर्शिनी, 11.ज्ञान, 12.क्रिया, 13.योग, 14.प्रहवि, 15.सत्य, 16.इसना और 17.अनुग्रह।

*कहीं पर 1.प्राण, 2.श्रधा, 3.आकाश, 4.वायु, 5.तेज, 6.जल, 7.पृथ्वी, 8.इन्द्रिय, 9.मन, 10.अन्न, 11.वीर्य, 12.तप, 13.मन्त्र, 14.कर्म, 15.लोक और 16.नाम।

16 कलाएं दरअसल बोध प्राप्त योगी की भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं। बोध की अवस्था के आधार पर आत्मा के लिए प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक चन्द्रमा के प्रकाश की 15 अवस्थाएं ली गई हैं। अमावास्या अज्ञान का प्रतीक है तो पूर्णिमा पूर्ण ज्ञान का।

19 अवस्थाएं :भगवदगीता में भगवान श्रीकृष्ण ने आत्म तत्व प्राप्त योगी के बोध की उन्नीस स्थितियों को प्रकाश की भिन्न-भिन्न मात्रा से बताया है। इसमें अग्निर्ज्योतिरहः बोध की 3 प्रारंभिक स्थिति हैं और शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्की 15 कला शुक्ल पक्ष की 01..हैं। इनमें से आत्मा की 16 कलाएं हैं।

आत्मा की सबसे पहली कला ही

विलक्षण है। इस पहली अवस्था या उससे पहली की तीन स्थिति होने पर भी योगी अपना जन्म और मृत्यु का दृष्टा हो जाता है और मृत्यु भय से मुक्त हो जाता है।

अग्निर्ज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम्।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥

अर्थात :जिस मार्ग में ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता हैं, दिन का अभिमानी देवता है, शुक्ल पक्ष का अभिमानी देवता है और उत्तरायण के छः महीनों का अभिमानी देवता है, उस मार्ग में मरकर गए हुए ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपयुक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाए जाकर ब्रह्म को प्राप्त होते हैं।- (8-24)

भावार्थ :श्रीकृष्ण कहते हैं जो योगी अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्लपक्ष, उत्तरायण के छह माह में देह त्यागते हैं अर्थात जिन पुरुषों और योगियों में आत्म ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, वह ज्ञान के प्रकाश से अग्निमय, ज्योर्तिमय, दिन के सामान, शुक्लपक्ष की चांदनी के समान प्रकाशमय और उत्तरायण के छह माहों के समान परम प्रकाशमय हो जाते हैं। अर्थात जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को जानना या देह से अलग स्वयं की स्थिति को पहचानना।

विस्तार से...

1.अग्निः-बुद्धि सतोगुणी हो जाती है दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव विकसित होने लगता है।

2.ज्योतिः-ज्योति के सामान आत्म साक्षात्कार की प्रबल इच्छा बनी रहती है। दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव ज्योति के सामान गहरा होता जाता है।

3.अहः-दृष्टा एवं साक्षी स्वभाव दिन के प्रकाश की तरह स्थित हो जाता है।

16 कला - 15कला शुक्ल पक्ष + 01 उत्तरायण कला = 16

1.बुद्धि का निश्चयात्मक हो जाना।

2.अनेक जन्मों की सुधि आने लगती है।

3.चित्त वृत्ति नष्ट हो जाती है।

4.अहंकार नष्ट हो जाता है।

5.संकल्प-विकल्प समाप्त हो जाते हैं। स्वयं के स्वरुप का बोध होने लगता है।

6.आकाश तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। कहा हुआ प्रत्येक शब्द सत्य होता है।

7.वायु तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। स्पर्श मात्र से रोग मुक्त कर देता है।

8.अग्नि तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। दृष्टि मात्र से कल्याण करने की शक्ति आ जाती है।

9.जल तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। जल स्थान दे देता है। नदी, समुद्र आदि कोई बाधा नहीं रहती।

10.पृथ्वी तत्व में पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हर समय देह से सुगंध आने लगती है, नींद, भूख प्यास नहीं लगती।

11.जन्म, मृत्यु, स्थिति अपने आधीन हो जाती है।

12.समस्त भूतों से एक रूपता हो जाती है और सब पर नियंत्रण हो जाता है। जड़ चेतन इच्छानुसार कार्य करते हैं।

13.समय पर नियंत्रण हो जाता है। देह वृद्धि रुक जाती है अथवा अपनी इच्छा से होती है।

14.सर्व व्यापी हो जाता है। एक साथ अनेक रूपों में प्रकट हो सकता है। पूर्णता अनुभव करता है। लोक कल्याण के लिए संकल्प धारण कर सकता है।

15.कारण का भी कारण हो जाता है। यह अव्यक्त अवस्था है।

16.उत्तरायण कला- अपनी इच्छा अनुसार समस्त दिव्यता के साथ अवतार रूप में जन्म लेता है जैसे राम, कृष्ण यहां उत्तरायण के प्रकाश की तरह उसकी दिव्यता फैलती है।

सोलहवीं कला पहले और पन्द्रहवीं को बाद में स्थान दिया है। इससे निर्गुण सगुण स्थिति भी सुस्पष्ट हो जाती है। सोलह कला युक्त पुरुष में व्यक्त अव्यक्त की सभी कलाएं होती हैं। यही दिव्यता है।

"64 प्राणायाम" की संकल्पना और परंपरा

"64 प्राणायाम" की संकल्पना विभिन्न योग ग्रंथों और परंपराओं से प्रेरित है, परंतु स्पष्ट रूप से एकल सूची बहुत कम ग्रंथों में मिलती है। अधिकतर मान्य ग्रंथ (जैसे हठयोग प्रदीपिका, घेरंड संहिता, शिव संहिता) मुख्यतः 8–15 प्रमुख प्राणायामों का उल्लेख करते हैं लेकिन तांत्रिक, नाथ और सिद्ध योग परंपराओं में विविध प्रकारों और संयोजनों को मिलाकर 64 प्रकार माने गए हैं यह मुख्य रूप से विभिन्न तकनीकों, गति, लक्ष्य (ध्यान, शक्ति, शुद्धि) के आधार पर वर्गीकृत हैं।

प्राणायाम के 64 प्रकारों की विस्तारित सूची (संयोजनों सहित)

मुख्य 8 प्राणायाम

1. नाड़ी शोधन
2. भस्त्रिका
3. कपालभाति
4. अनुलोम विलोम
5. शीतली
6. शीतकारी
7. भ्रामरी
8. सूर्या भेदी / चंद्र भेदी

मुख्य वेरिएशन्स और संयोजनः (कुंभक-आधारित)

9. सहज कुम्भक
10. अंतर कुम्भक
11. बाह्य कुम्भक
12. समाधि कुम्भक
13. केवली कुम्भक
14. सूर्य कुम्भक
15. चंद्र कुम्भक

गतियों पर आधारित

16. मंदगति प्राणायाम
17. मध्यम गति प्राणायाम
18. तीव्र गति प्राणायाम
19. रुक-रुक कर श्वास लेना
20. उच्छ्वास-निःश्वास का लहरात्मक अभ्यास

मुद्रा संयोजन के साथ

21. प्राणायाम + महा मुद्रा
22. प्राणायाम + अश्विनी मुद्रा
23. प्राणायाम + मूलबंध
24. प्राणायाम + जालंधर बंध
25. प्राणायाम + उड्डियान बंध
26. प्राणायाम + महा बंध

ध्वनियों के साथ

27. ओंकार प्राणायाम
28. राम नाम प्राणायाम
29. सो-हं प्राणायाम
30. ऊं नाद प्राणायाम
31. भ्रामरी + ऊँ प्राणायाम

तत्वों पर आधारित

32. अग्नि प्राणायाम
33. जल प्राणायाम
34. वायु प्राणायाम
35. पृथ्वी प्राणायाम
36. आकाश प्राणायाम

चक्र ध्यान के साथ

37. मूलाधार ध्यान प्राणायाम
38. स्वाधिष्ठान ध्यान प्राणायाम
39. मणिपुर ध्यान प्राणायाम
40. अनाहत ध्यान प्राणायाम
41. विशुद्ध ध्यान प्राणायाम
42. आज्ञा ध्यान प्राणायाम
43. सहस्रार ध्यान प्राणायाम

विशेष परंपरागत अभ्यास

44. नादानुसंधान प्राणायाम
45. सुषुम्ना जागरण प्राणायाम
46. चंद्रकलाद्ध प्राणायाम
47. पंचवायु नियमन
48. त्रिवेणी प्राणायाम
49. चित्त-नाड़ी प्राणायाम
50. ब्रह्मरंध्र प्राणायाम

तांत्रिक और योगिक संयुक्त रूप

51. कुंडलिनी प्राणायाम
52. कालाग्नि प्राणायाम
53. श्रीविद्या प्राणायाम
54. सिद्धासन प्राणायाम
55. ध्यानपूर्वक प्राणायाम
56. त्राटक + प्राणायाम
57. मन्त्र-युक्त प्राणायाम
58. पंचप्राण जागरण प्राणायाम

साधक स्तर पर आधारित

59. प्रारंभिक प्राणायाम
60. मध्यम स्तर प्राणायाम
61. उन्नत प्राणायाम
62. ऋतु विशेष प्राणायाम
63. रोग विशेष प्राणायाम
64. मोक्षगामी प्राणायाम

नोटः यह सूची संयोजन + गूढ़ परंपराओं को जोड़कर बनाई गई है। यह अधिक उपयोगी होगी यदि आप इसे वर्गीकृत प्रैक्टिस के तौर पर अपनाएं।

(मतलब 64 दिन = एक साइलेंट शक्तिवर्धक यात्रा)

भांग और गांजे का चमत्कार

1914 का वर्ष, प्रथम विश्व युद्ध और अमेरिकी डॉलर के लिए "भांग" की खेती करने वाले किसान

औद्योगिक भांग सिर्फ एक कृषि संयंत्र नहीं है! यह तेल और डॉलर के खिलाफ मारक है!

गांजा कैसे प्रतिबंधित किया गया था ?

1. भांग का एक टुकड़ा खेत में 25 एकड़ जंगल के बराबर ऑक्सीजन पैदा करता है।

२. एक एकड़ गांजा 4 एकड़ पेड़ों के बराबर कागज का उत्पादन कर सकता है।

3. जहाँ भांग को 8 बार कागज में बदला जा सकता है, वहीं लकड़ी को ३ बार कागज में बदला जा सकता है।

4. गांजा 4 महीने में उगता है, पेड़ 20-50 साल में।

5. कैनबिस विकिरण का एक वास्तविक पकड़ने वाला पौधा है।

6. भांग को दुनिया में कहीं भी उगाया जा सकता है और इसके लिए बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इसे कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती है।

7. यदि भांग का कपड़ा व्यापक हो जाता है, तो कीटनाशक उद्योग पूरी तरह से गायब हो सकता है।

8. पहली जींस भांग से बनी थी; यहाँ तक कि "कैनवास" शब्द भी भांग उत्पादों को दिया गया नाम है। गांजा रस्सियों, डोरियों, बैगों, जूतों, टोपियों के निर्माण के लिए भी एक आदर्श पौधा है।

9. भाँग, एड्स और कैंसर के उपचार में कीमोथेरेपी और विकिरण के प्रभाव को कम करता हो; यह गठिया, हृदय, मिर्गी, दमा, पेट, अनिद्रा, मनोविज्ञान और रीढ़ की बीमारियों जैसे कम से कम 250 रोगों में दवाई के लिए प्रयोग किया जा है।

10. भाँग के बीज का प्रोटीन मूल्य बहुत अधिक होता है और दो फैटी एसिड इसके अलावा प्रकृति में और कहीं नहीं पाए जाते हैं।

11. सोयाबीन की तुलना में गांजा का उत्पादन और भी सस्ता है।

12. जिन जानवरों को भांग खिलाया जाता है उन्हें हार्मोनल सप्लीमेंट की आवश्यकता नहीं होती है।

13. सभी प्लास्टिक उत्पादों को भांग से बनाया जा सकता है और भांग प्लास्टिक का दुबारा प्रकृति में वापस आना बहुत आसान है।

14. कार की बॉडी गांजा की बनी हो तो यह स्टील से 10 गुना अधिक मजबूत होगी।

15. इसका उपयोग इमारतों के इन्सुलेशन के लिए भी किया जा सकता है; यह टिकाऊ, सस्ता और लचीला है।

16. गांजा से बने साबुन और सौंदर्य प्रसाधन पानी को प्रदूषित नहीं करते हैं; इसलिए यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल है।

अमेरिका में 18वीं शताब्दी में इसका उत्पादन अनिवार्य था लेकिन अब स्थिति इसके उलट है। कहाँ से? :- डब्ल्यू आर. हर्स्ट-1900 के दशक में अमेरिका में समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और मीडिया के मालिक थे। उनके पास जंगल थे और कागज का उत्पादन करते थे। अगर कागज भांग से बना होता, तो उसे लाखों का नुकसान हो सकता था।

रॉकफेलर विश्व के सबसे धनी व्यक्ति थे। एक तेल कंपनी थी। बेशक, जैव ईंधन, भांग का तेल, उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। मेलॉन इंयूपॉन्ट में एक प्रमुख शेयरधारक था और उसके पास पेट्रोलियम उत्पादों से प्लास्टिक के उत्पादन के लिए एक पेटेंट था और भांग उद्योग उसके बाजार को खतरे में डाल रहा था। बाद में मेलॉन अमेरिकी राष्ट्रपति हूवर के कोषागार के सचिव बने।

इसने ऊपर जिन बड़े नामों के बारे में बात की उन्होंने बैठकों में तय किया कि भांग दुश्मन है और उन्होंने उसका सफाया कर दिया।

मीडिया के माध्यम से, उन्होंने मारिजुआना शब्द के साथ-साथ लोगों के दिमाग में एक जहरीली दवा के रूप में मारिजुआना का इंजेक्शन लगाया है। और उसके बाद

1. भांग की दवाओं को बाजार से वापस ले लिया गया है और उन की जगह आज इस्तेमाल होने वाली रासायनिक दवाओं ने ले लिया।

२. कागज उत्पादन के लिए जंगलों को काटा जा रहा है।

३. कीटनाशक और कैंसर का नशा बढ़ रहा है और फिर इसने अपनी दुनिया को प्लास्टिक कचरे, खतरनाक कचरे से भर दिया।

भारतीय ज्ञान प्रणाली के नाम पर संघी दर्शन को पढ़ाने और वर्णाश्रमी समाज को बनाने की साजिश

जी. रामकृष्णन, अनुवाद : संजय पराते)

भारत में पीएचडी शोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को यूजीसी-नेट (राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा) देनी होती थी, जो 2024-25 तक भारतीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में 'सहायक प्रोफेसर' तथा 'जूनियर रिसर्च फेलोशिप और सहायक प्रोफेसर' के लिए भारतीय नागरिकों की पात्रता निर्धारित करने के लिए एक परीक्षा थी। 2024 में, केंद्र सरकार ने शोध कार्यक्रमों के मानकीकरण और गुणवत्ता में सुधार के नाम पर पीएचडी प्रवेश के लिए नेट स्कोर को एक प्रमुख मानदंड बना दिया है। राज्य सरकारों के उच्च शिक्षा विभागों द्वारा सार्वजनिक धन से प्रबंधित राज्य संचालित विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की संख्या केंद्रीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों से कहीं अधिक है। ये संस्थान अब तक अपने स्वयं के स्थापित चयन मानदंडों और प्रक्रियाओं के माध्यम से पीएचडी शोध कार्यक्रमों के लिए छात्रों का चयन कर रहे थे। अब, यूजीसी के नए आदेशों के साथ, राज्य स्तरीय संस्थान धीरे-धीरे अपनी चयन प्रक्रिया में नेट स्कोर को शामिल करने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इस तरह की अत्यधिक केंद्रीकरण की प्रक्रिया गरीब और वंचित वर्गों के छात्रों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के तबकों के छात्रों को, शोध करियर अपनाने से रोकेगी।

एक ओर जहाँ केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने के प्रयास में पीएचडी प्रवेश के लिए भी नेट अनिवार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर, वही केंद्र सरकार आईआईटी में प्रवेश को इसका भयानक अपवाद बना रही है। केंद्र सरकार ने 'सेतुबंध विद्वान योजना' नामक एक नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पारंपरिक गुरुकुलों में संस्कृत की शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई) के अंक अनिवार्य नहीं हैं। 'सेतुबंध विद्वान योजना' पारंपरिक गुरुकुलों में अध्ययन करने वाले और बिना किसी औपचारिक अकादमिक डिग्री वाले छात्रों को मान्यता प्राप्त शैक्षणिक योग्यताएँ हासिल करने और प्रमुख आईआईटीज़ में शोध के लिए उदार छात्रवृत्ति प्राप्त करने के अवसर प्रदान करती है। 29 जुलाई के 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, यह योजना "शिक्षा मंत्रालय द्वारा समर्थित और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के भारतीय ज्ञान प्रणाली (इंडियन नॉलेज सिस्टम - आइकेएस) प्रभाग द्वारा क्रियान्वित की जाएगी। यह योजना 18 विषय क्षेत्रों में 65,000 रुपये प्रति माह तक की फेलोशिप प्रदान करती है, जिसमें आयुर्वेद से लेकर संज्ञानात्मक विज्ञान तक और वास्तुकला से लेकर राजनीतिक सिद्धांत तक, व्याकरण से लेकर रणनीतिक अध्ययन तक और प्रदर्शन कला से लेकर गणित, भौतिकी और स्वास्थ्य विज्ञान तक शामिल हैं।"

शोध कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए मूल पात्रता, हाईस्कूल और उच्च शिक्षा के 10+2+3+2 वर्ष हैं, और अब इन 15 वर्षों के कठोर वैज्ञानिक अध्ययनों के ऊपर, केंद्र सरकार ने नेट स्कोर को यह कहते हुए अनिवार्य कर दिया है कि शोध में गुणवत्ता के मानकीकरण के लिए यह बहुत आवश्यक है। वही सरकार अब यह कह रही है कि किसी मान्यता प्राप्त गुरुकुल में कम से कम पाँच वर्षों के कठोर अध्ययन और शास्त्रों या पारंपरिक ज्ञान में स्पष्ट उत्कृष्टता के आधार पर हासिल पात्रता, आईआईटी के शोध कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पर्याप्त है। पीएचडी प्रवेश के लिए अनिवार्य नेट प्रक्रिया के माध्यम से कौन बाहर होगा और सेतुबंध विद्वान योजना की भयावह योजना के माध्यम से कौन शोध कार्य में शामिल हो जाएगा? वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रति केंद्र सरकार का यह विरोधाभासी दृष्टिकोण, वास्तव में आरएसएस की उसी परियोजना में अपना योगदान देता है, जो जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था पर आधारित एक शाश्वत विभाजित समाज का निर्माण करना चाहती है। नई नेट आधारित प्रवेश प्रणाली, सदियों से चले आ रहे उत्पीड़न के कारण समाज के सबसे निचले तबके में फंसे लोगों के लिए शोध के अवसरों तक पहुँच को बेहद कठिन बना देगी। यानी, यह नेट गरीब और हाशिए पर पड़े वर्गों के छात्रों को शोध क्षेत्र से बाहर कर देगा। साथ ही, नेट समाज के कुलीन वर्ग के छात्रों के लिए शोध के क्षेत्र में प्रवेश के अवसर बढ़ाता है। सेतुबंध विद्वान योजना एक ऐसी योजना है, जो आईआईटी में अत्यधिक मांग वाले शोध के अवसरों को संस्कृत जानने वाले एक खास तबके को सोने की थाली में रखकर परोसा जा रहा है। यह तबका वैदिक शास्त्रों पर अपना अधिकार जताता है। यह स्पष्ट है कि वह तबका कौन-सा है?

गुरुकुल शिक्षा प्रणाली शिक्षा की एक प्राचीन प्रणाली थी, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति वैदिक काल में, लगभग 1500 ईसा पूर्व में हुई थी। यह मौखिक परंपरा पर आधारित प्रणाली थी, जो कंठस्थ करने और पाठ करने पर केंद्रित प्रणाली है। यह एक ऐसी प्रणाली थी, जो गैर-ब्राह्मणों को शिक्षा प्रणाली से खुले तौर पर बाहर रखती थी। हमने कुख्यात एकलव्य-द्रोणाचार्य की कहानी सुनी है, जो जाति और वर्णाश्रम व्यवस्था की क्रूरता की मजबूत गवाही देती है। आमतौर पर यह दावा किया जाता है कि गुरुकुल अध्ययन में भाषा, व्याकरण, कुछ विज्ञान और गणित आदि विषयों की एक श्रृंखला शामिल होती है। बहरहाल, मंत्र याद करना और मंत्र जपना ही उन गुरुकुलों में 'सीखना' कहलाता है। अब इन मंत्र याद करने और जपने वाले गुरुकुल 'शिक्षार्थियों' को आईआईटी के शोध क्षेत्रों में अनुमति देने का अर्थ है – आईआईटी द्वारा शिक्षा और अनुसंधान में अब तक हासिल किए गए वैश्विक मानकों को कमजोर करना। इससे भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र और मानव पूंजी को भारी नुकसान होगा, जिससे राष्ट्र के औद्योगिक और आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होगी।

हमारा भारतीय संविधान प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य के रूप में वैज्ञानिक सोच के विकास पर ज़ोर देता है। अनुच्छेद-51ए(एच) भारत के प्रत्येक नागरिक को 'वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद और जिज्ञासा एवं सुधार की भावना विकसित करने' का आदेश देता है। यह आदेश तर्कसंगत सोच, आलोचनात्मक अन्वेषण और वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से वैज्ञानिक प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित समाज का आह्वान करता है। बहरहाल, आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा अपनी नई शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से, एक तर्कसंगत और समतावादी समाज सुनिश्चित करने के लिए वर्तमान में मौजूद वैज्ञानिक प्रणालियों को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, और उनकी जगह 'भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ' स्थापित करके एक मनुवादी समाज, जो तर्कहीन और असमान समाज होगा, स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यही आरएसएस का सौ साल पुराना सपना है।

महाराष्ट्र का एक विश्वविद्यालय, एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय है, जो खुद को दक्षिण एशिया का पहला महिला विश्वविद्यालय होने का दावा करता है और जिसकी स्थापना 1916 में हुई थी। इसने एनईपी-2020 के अनुसार यूजी कोर्स के लिए पाठ्यक्रम तैयार किया है, जिसका नाम "भारतीय ज्ञान प्रणाली की शुरुआत" है। उसने वैदिक धर्म और षड दर्शन (हिंदू धर्म के भीतर भारतीय दर्शन के छह रूढ़िवादी स्कूल) और वास्तु-विद्या को पढ़ने के लिए अपने पाठ्यक्रम का विषय बनाया है! यह दर्शाता है कि जब हम तथाकथित 'भारतीय ज्ञान प्रणालियों' को अपने शैक्षिक, वैज्ञानिक और अनुसंधान संस्थानों पर कब्जा करने की अनुमति देते हैं, तो हमारे लिए उससे क्या हासिल होता है। उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में "भारतीय ज्ञान प्रणाली" को शामिल करने के लिए दिशा-निर्देश 13.06.2023 को जारी किए गए थे। ये दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि यूजी या पीजी कार्यक्रम में नामांकित प्रत्येक छात्र को कुल पाठ्यक्रम का कम से कम 5% आईकेएस (भारतीय ज्ञान प्रणाली) पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इसका क्या अर्थ हैं? यूजी/पीजी प्रोग्राम में दाखिला लेने वाले हर छात्र को भारतीय ज्ञान प्रणाली (आईकेएस) के बहाने आरएसएस के दर्शन को सीखने और अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। 2014 से आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार हिंदू राष्ट्र की स्थापना के एजेंडे को लागू करने में जी-जान से जुटी हुई है।

एम.एस. गोलवलकर वह व्यक्ति थे, जिन्होंने आरएसएस की वैचारिक नींव रखी थीं। उन्होंने मनु को 'दुनिया का पहला और महान विधि निर्माता' बताया था, जिसने 'अपनी संहिता में दुनिया के सभी लोगों को हिंदू धर्म अपनाने और इस देश के 'सबसे वरिष्ठ' ब्राह्मणों के पवित्र चरणों में अपने कर्तव्यों का ज्ञान प्राप्त करने का निर्देश दिया।' आरएसएस ने भारत की संविधान सभा से मनुस्मृति के सिद्धांतों के आधार पर संविधान बनाने का आग्रह किया था, जिसे डॉ. अंबेडकर और संविधान सभा ने खारिज कर दिया था। संविधान के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप से व्यथित होकर, एम.एस. गोलवलकर ने सार्वजनिक रूप से कहा कि भारतीय संविधान 'विदेशी' है। अब, नई शिक्षा नीति के माध्यम से, आरएसएस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार भारत को ठीक इसी ओर ले जा रही है -- अर्थात, मनुवादी हिंदू राष्ट्र की ओर -- जिसमें एक वर्णाश्रम समाज होगा, जो नवउदारवाद की आवश्यकताओं के अनुकूल होगा।

किसी देश की शिक्षा नीति उसके युवाओं और देश के भविष्य का निर्धारण करती है। इसके अलावा, भारत में शिक्षा एक समवर्ती विषय है। लेकिन, भाजपा सरकार ने इस बारे में न तो संसद में चर्चा की और न ही नई शिक्षा नीति के संबंध में राज्यों से ही कोई परामर्श किया है।

भारत की लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष ताकतों को आरएसएस की इस साजिश के खिलाफ अथक युद्ध छेड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए।

(लेखक माकपा पोलिट ब्यूरो के पूर्व सदस्य और कंट्रोल कमीशन के अध्यक्ष हैं।

रक्षाबंधन का पावन पर्व सिर्फ भाई-बहन का रिश्ता नहीं, बल्कि विश्वास, सम्मान और संस्कार की अनमोल डोर है।स्वर्गीय दीदी सुषमा स्वराज जी ने हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह स्नेह दिया। रक्षाबंधन के अवसर पर उनकी सुपुत्री अपनी भांजी सुप्रसिद्ध अधिवक्ता एवं नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की लोकप्रिय सरल एवं सौम्य सांसद सुश्री बांसुरी स्वराज जी से राखी का पवित्र रक्षा सूत्र बँधवाया एवं उन्हें स्वस्थ सुखी यशस्वी जीवन का आशीर्वाद दिया । यह पवित्र धागा मुझे सिर्फ बहन की रक्षा का नहीं, बल्कि अपने देश और समाज की सुरक्षा का संकल्प भी याद दिलाता है-राजेश भाटिया । अपने माता पिता बहन भाइयों एवं बुजुर्गों का सम्मान करें।

सिविल लाइन जोन के अध्यक्ष ने राखी बंधवाई

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। सिविल लाइन जोन के अध्यक्ष ने क्षेत्र की महिलाओं से राखी बंधवाई क्षेत्र की महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं दी और बताया कि यह त्यौहार एक भाई बहन का त्यौहार होता है इस त्यौहार को हमें बनाना जरूरी है इस त्यौहार का उदेश्य है कि अपनी बहनों को लेकर एक सुरक्षा की दीवार बनकर एक भाई खड़ा रहता है वैसे ही क्षेत्र के महिलाओं के साथ क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक दीवार बनकर खड़े गुलाब सिंह राठौड़ जो की मुकंदपुर वार्ड से निगम पार्षद है और साथ ही सिविल लाइन जोन के अध्यक्ष भी है उन्होंने बताया कि हम महिलाओं के पास हम वोट लेने भी जाते हैं व तमाम महिलाओं के कार्य हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें क्षेत्र की महिलाओं को लेकर जागरूक अभियान भी कहीं ना कहीं चलते हैं और महिला सुरक्षा को लेकर भी समय-समय पर तमाम कार्यक्रम करते हैं व रक्षाबंधन के दिन भी हम इन बहनों से राखी बंधवा इन्हें एक विश्वास दिलाते हैं कि हम तहे दिल से आपके साथ खड़े हैं और यह राखी बंधवाने के बाद साफ तौर पर जाहीर हो जाता है की मे आपके साथ एक ढाल बनकर खड़ा हु तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी समस्या है आपको भी दिक्कत आती है तो आप वे निश्चित से अपने भाई गुलाब सिंह राठौड़ को बता सकते हैं साथ ही गुलाब सिंह ने क्षेत्र के महिलाओं से राखी बंधवा उन्हें उपहार के तौर पर एक-एक साड़ी भेट की साथ ही बताया कि आज हम अपने वार्ड के जहांगीरपुरी में रक्षाबंधन बना रहे हैं और कल हम मुकंदपुर में हमारे क्षेत्र के महिलाओं के साथ हर साल की तरह रक्षाबंधन का त्योहार बनाएंगे।

जलेबी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है : संजय बाटला

समोसा, कचौड़ी, पोहा और जलेबी से तो देश लाखों साल से भारत देश में कोई बीमार नहीं हुआ। पिछले 30 वर्षों में बर्गर, पिज्जा, मोमोज और चाउमिन जैसे चाइनीज और अमेरिकन खाने ने देश के स्वास्थ्य पर ग्रहण जरूर लगा दिया है।

यह इन्हीं का समोसा जलेबी के विरुद्ध उसी प्रकार का एक सुनियोजित षडयंत्र है, जैसा पहले दीपावली के समय भारतीय मिठाइयों में कमी बताकर चॉकलेट और पैक्ड विदेशी सामानों के गिफ्ट का चलन कराया गया था। जलेबी खाने से बीमारी का इलाज आयुर्वेद में है। वास्तव में जलेबी रोग हरण करने वाली है। विधि विधान से बनी जलेबी न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी है। इसलिए देशीय भोजन सामग्री की उपेक्षा करने से पूर्व विदेशी के पीछे छिपे पाखंड व षड़यंत्र पर भी चर्चा करें। मोमोज, चाउमिन, बर्गर, पिज्जा, सैंडविच, पेटीज आदि छोड़ो और उचित मात्रा में जलेबी खाओ। दूध पियो शक्ति देगा। दूध जलेबी की तो स्वास्थ्य के हिसाब से जोड़ी भी है।

दिल्ली में भारी बारिश का असर हवाई उड़ानों पर आईजीआई एयरपोर्ट से 300 से अधिक फ्लाइट्स में हुई देरी

शनिवार को दिल्ली में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया जिससे हवाई अड्डे पर 300 से अधिक उड़ानें प्रभावित हुईं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर उड़ानों में देरी हुई हालांकि किसी का मार्ग परिवर्तित नहीं किया गया। एयरलाइंस ने यात्रियों को उड़ान की जानकारी लेने की सलाह दी। एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को हिंडन में जगह न मिलने पर आईजीआई पर उतरना पड़ा।

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया। वहीं खराब मौसम के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर 300 से अधिक उड़ानों में देरी हुई। एक अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआई) पर भारी बारिश के कारण किसी भी उड़ान का मार्ग परिवर्तित नहीं किया गया।

शनिवार तड़के से हो रही वर्षा का असर आईजीआई एयरपोर्ट से संचालित होने वाली उड़ानों पर देखा गया। प्रस्थान से जुड़ी 63 प्रतिशत उड़ानें विलंबित रहीं। इनमें करीब करीब एक तिहाई उड़ानें ऐसी थीं, जिनके प्रस्थान में एक घंटा या इससे अधिक का विलंब दर्ज किया गया। विलंबित उड़ानों में औसत विलंब का समय करीब 20 मिनट रहा।

वहीं आगमन की बात करें तो करीब 20 प्रतिशत उड़ानें विलंब की चपेट में आईं। औसत विलंब के मामले में यहां प्रस्थान के मुकाबले स्थिति बेहतर रही। यहां औसत विलंब करीब पांच मिनट दर्ज किया गया।

उधर मौसम को देखते हुए सभी प्रमुख एयरलाइंस की ओर से इंटरनेट मीडिया पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी

जारी होती रही। सभी एयरलाइंस ने यात्रियों से कहा कि वे एयरपोर्ट के लिए रवाना होने से पहले एक बार उड़ान की जानकारी ले लें। एयरलाइंस से यात्रियों से कहा कि वर्षा के कारण दिल्ली की सड़कों पर जाम व जलभराव के कारण एयरपोर्ट तक का सफर लंबा हो सकता है, लिहाजा अतिरिक्त समय लेकर चलें।

हिंडन की उड़ान फिर आईजीआई पर डाइवर्ट

एअर इंडिया एक्सप्रेस की एक उड़ान को शनिवार को फिर डाइवर्जन का सामना करना पड़ा। इसकी वजह हिंडन एयरपोर्ट के बे एरिया में पार्किंग के लिए विमान को जगह नहीं मिलना रहा। बाद में एटीसी की अनुमति से विमान ने आइजीआइ एयरपोर्ट से लैंडिंग की। विमान को वाराणसी से हिंडन के बीच की यात्रा करनी थी।

आईजीआई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद यात्री बस से हिंडन के लिए रवाना हुए। उड़ान संख्या आइएक्स2978 से जुड़े इस प्रकरण को एक यात्री एक्स पर साझा करते हुए अपनी नाराजगी जताई। बाद में एअर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने हैंडल से इसपर खेद प्रकट किया।

धारा 341 और दलित मुसलमान

हाफ़िज़ ग़ुलाम सरवर

भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और ऐसा देश माना जाता है जहां संविधान हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है। यहां धर्म, जाति, रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव को संविधान में स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया गया है। लेकिन जब हम दलित मुसलमानों के मुद्दे को देखते हैं तो यह दावा अपनी सच्चाई खो बैठता है। दलित मुसलमान, यानी वे मुसलमान जो दलित जातियों से ताल्लुक रखते हैं, दशकों से अपने संवैधानिक अधिकारों, खासकर आरक्षण के अधिकार से वंचित हैं। यह वह तबका है जो न केवल सामाजिक रूप से पिछड़ा है बल्कि राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर भी उपेक्षित है।

इस्लाम का मूल संदेश समानता, भाईचारा और जात-पात की समाप्ति पर आधारित है। जब 11वीं और 12वीं सदी ईस्वी में इस्लाम भारत में आया तो अपने साथ कुरआन और सुन्नत की वह शिक्षाएं लाया जो सबको एक ही पंक्ति में खड़े होने का सबक देती हैं। लेकिन भारत में गहराई से जड़ें जमाए हुए जाति व्यवस्था मुसलमानों में भी समा गई। धीरे-धीरे मुसलमानों के भीतर भी वही जातियां और सामाजिक वर्गीकरण मौजूद हो गए जो हिंदू समाज में पाए जाते हैं। आज भी धोबी, भंगी, कुम्हार, नाई, लुहार जैसी जातियां मुसलमानों में पाई जाती हैं, हालांकि उनके नाम बदलकर कस्सार, हवारी, मेहतर या दूसरे खिताब रख दिए गए। हकीकत यह है कि इन मुसलमानों का सामाजिक दर्जा वही है जो हिंदू समाज में दलित जातियों का है। इसी वजह से उन्हें 'दलित मुसलमान' कहा जाता है और हाल के वर्षों में 'पसमांदा' शब्द प्रचलित हो गया है, जिसे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस्तेमाल किया है।

दलित मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी 10 अगस्त 1950 को हुई जब पंडित जवाहर लाल नेहरू के दौर में एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया। इस आदेश के मुताबिक केवल वही दलित जातियां अनुसूचित जाति (SC) के आरक्षण की हकदार होंगी जो हिंदू धर्म से जुड़ी हैं। अगर कोई दलित मुसलमान, ईसाई या कोई और धर्म अपना ले तो वह आरक्षण के अधिकार से वंचित हो जाएगा। बाद में 1956 में इस आदेश में संशोधन कर सिख धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण दिया गया और 1990 में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित भी इसमें शामिल हो गए, लेकिन मुसलमान और ईसाई दलित आज तक इस सूची से बाहर हैं। यह साफ विरोधाभास है कि अगर आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाता तो उससे वंचित करना भी धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए।

यह भेदभावपूर्ण नीति दलित मुसलमानों को दोहरी पसमांदगी में धकेलती है। वे एक तरफ सदियों पुरानी सामाजिक नाइंसाफियों का शिकार हैं और दूसरी तरफ धार्मिक आधार पर संवैधानिक सुविधाओं से वंचित हैं। नतीजतन शिक्षा, रोज़गार, आवास और राजनीति में उनकी स्थिति बद से बदतर है। यही वजह है कि हर साल 10 अगस्त को देशभर में कई दलित मुस्लिम और ईसाई संगठन इस दिन को 'काला दिवस' के रूप में मनाते हैं। दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन होता है। ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा जैसे संगठन वर्षों से सरकार से यह मांग करते आ रहे हैं कि दलित मुसलमानों और ईसाइयों को भी संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत आरक्षण दिया जाए।

दलित मुसलमानों के मुद्दे को न्यायिक स्तर पर भी उठाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें 1950 के राष्ट्रपति आदेश को चुनौती दी गई, जिसके तहत केवल हिंदू, सिख और बाद में बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलितों को ही आरक्षण का अधिकार दिया गया था। 2004 में जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बावजूद जाति का सामाजिक प्रभाव खत्म नहीं होता। इसलिए मुस्लिम और ईसाई दलितों को भी वही संवैधानिक आरक्षण मिलना चाहिए जो अन्य दलितों को मिलता है। इसी तरह सच्चर समिति (2006) और रंगनाथ मिश्रा आयोग (2007) ने भी मुसलमानों की सामाजिक और आर्थिक पसमांदगी को स्वीकार करते हुए उन्हें आरक्षण समेत अन्य सुविधाएं देने की सिफारिश की थी। अफसोस की बात यह है कि इन महत्वपूर्ण रिपोर्टों को आज तक केवल कागज़ों में ही रखा गया है और उन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

इसके अलावा राजनीतिक पार्टियां भी इस मुद्दे पर वोट बैंक की राजनीति करती आई हैं। चुनाव के समय दलित मुसलमानों की बात तो की जाती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद उनके मुद्दों को हमेशा पीछे डाल दिया जाता है। कुछ राज्यों में दलित मुसलमानों को ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत रखा गया है, लेकिन यह दर्जा SC के आरक्षण की तुलना में बहुत कमजोर और सीमित है। यह कदम केवल सतही हमदर्दी दिखाने के बराबर है।

भारत का संविधान सभी के लिए समान अवसर की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 और 16 में स्पष्ट रूप से भेदभाव की मनाही की गई है। लेकिन 1950 का राष्ट्रपति आदेश आज भी इस समानता के सिद्धांत के खिलाफ खड़ा है। धर्म के आधार पर किसी नागरिक को उसके अधिकार से वंचित रखना एक सेक्युलर और लोकतांत्रिक राज्य के सिद्धांतों के खिलाफ है। यह केवल कानूनी ही नहीं बल्कि नैतिक विफलता भी है।

समय आ गया है कि सरकार अनुच्छेद 341 में संशोधन करे और दलित मुसलमानों व ईसाइयों को भी उनके संवैधानिक अधिकार लौटाए। अगर हम वास्तव में समानता पर आधारित, सेक्युलर और न्यायप्रिय देश चाहते हैं तो हमें इस भेदभाव की दीवार को गिराकर सबको बराबरी के स्तर पर लाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक भारत का लोकतंत्र और सेक्युलरिज़्म अधूरा सपना ही रहेगा, जिसमें कुछ नागरिकों को पूरा अधिकार और कुछ को अधूरा न्याय मिलता है।

जेल और पुलिस लाइन समेत कानपुर में धूमधाम से मना रक्षाबंधन का त्योहार

सुनील बाजपेई

कानपुर। शनिवार को यहां भाई-बहन के प्रेम पर्व रक्षाबंधन का त्योहार जेल और रिजर्व पुलिस लाइन सहित पूरे जिले में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया।

इस मौके पर पारंपरिक रस्मों को निभाते हुए बहनों ने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध उनसे रक्षा का वचन भी लिया।

इसके लिए बहनों ने शुभ मुहूर्त में कुमकुम, अक्षत, रक्षा सूत्र, मिठाई, सूखा नारियल से पूजा का थाल सजाया। इसके बाद भाई के माथे पर प्रेम का टीका लगा ,आरती उतारी रक्षासूत्र बांधा। साथ ही उनकी लंबी उम्र और कामयाबी की कामना भी की। बदले में भाईयों ने भी अपनी प्यारी बहन को उपहार स्वरूप उपहार देकर

पुलिसकर्मियों ने बहनों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।

हमेशा साथ निभाने का वादा किया।

इसी क्रम में दबौली की समीक्षा रुची मनोहर राज मिश्रा की बेटी नंदिनी मीठी ने भी भाई बुद्धि निकेत कृष्णा मिश्रा, कार्तिकेय त्रिपाठी हनू ,समक्ष नंदन मिश्रा और देवांश बाजपेई राघव को भी तिलक लगा, राखी बांध और मिठाई खिला इस परंपरा का निर्वहन किया। इस अवसर पर चारो ने बच्ची नंदिनी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद भी लिया।

आज राखी के त्योहार पर दिनभर घरों में रक्षा सूत्र बांधने को लेकर लोगों में उत्साह भी दिखाई दिया। विवाहित महिलाओं ने अपने पीहर पहुंच कर भाइयों को रक्षा सूत्र बांध उनसे रक्षा का वचन और बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लिया। राखी बांधने यह क्रम पुलिस लाइन, थानों और जेल में भी चला।

आज़ाद भारत और 15 अगस्त

शम्भू शरण सत्यार्थी

हर साल जब 15 अगस्त आता है, पूरा देश गर्व और देशभक्ति की भावना से भर जाता है। यह दिन भारत के इतिहास का सबसे सुनहरा दिन है क्योंकि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश गुलामी की ज़ंजीरों को तोड़कर आज़ाद हुआ था। यह दिन केवल एक तारीख नहीं है, यह बलिदान, संघर्ष और देशप्रेम की याद दिलाने का दिन है।

भारत पर लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का राज रहा। उन्होंने हमारे देश के लोगों पर अत्याचार किए, हमारे संसाधनों का शोषण किया, और हमें हमारे ही देश में कमजोर और असहाय बना दिया। उस समय भारतीयों के पास ना तो बोलने की आज़ादी थी, ना ही अपने हक के लिए लड़ने की।

अंग्रेजों के खिलाफ कई छोटे-बड़े आंदोलन हुए लेकिन 1857 का स्वतंत्रता संग्राम पहला बड़ा प्रयास था जिसमें रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब जैसे कई वीरों ने भाग लिया। इसके बाद कई आंदोलनों ने आज़ादी की ज्वाला को और भी प्रज्वलित किया।

भारत की आज़ादी आसान नहीं थी। इसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने जेलें झेली, यातनाएँ सहीं और अपनी जान तक कुर्बान कर दी। महात्मा गांधी ने 'सत्य और अहिंसा' का मार्ग अपनाकर देश को एकजुट किया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने फाँसी के फंदे को हँसते-हँसते गले लगाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाकर अंग्रेजों से लोहा लिया। सरदार पटेल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद जैसे कई नेता आज़ादी की इस लड़ाई के स्तंभ बने। इन सबके प्रयासों और त्याग के कारण ही हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली।

15 अगस्त, भारत का स्वतंत्रता दिवस उन अनगिनत बलिदानों और प्रेरक कहानियों का प्रतीक है जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई।

महात्मा गांधी ने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों के माध्यम से ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अनूठा आंदोलन चलाया। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ, यह गांधीजी के दृढ़ विश्वास और नेतृत्व का परिणाम था। उनका दांडी नमक मार्च (1930) एक ऐसा प्रेरक प्रसंग है, जिसने न केवल भारतीयों को एकजुट किया बल्कि विश्व को अहिंसा की ताकत दिखाई। इस मार्च में गांधीजी ने 24 दिनों तक 390 किलोमीटर की यात्रा की और समुद्र तट पर नमक बनाकर ब्रिटिश नमक कानून का उल्लंघन किया। यह छोटा-सा कदम स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा प्रतीक बन गया।

23 वर्षीय युवा क्रांतिकारी भगत सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। 1929 में उन्होंने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम फेंका लेकिन इसका उद्देश्य किसी को मारना नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार का ध्यान भारतीयों की मांगों की ओर खींचना था। उनके नारे ₹इंकलाब जिंदाबाद₹ ने लाखों युवाओं को प्रेरित किया। 15 अगस्त 1947 को भले ही भगत सिंह इसे देखने के लिए जीवित न रहे, लेकिन उनकी कुर्बानी ने स्वतंत्रता की नींव को मजबूत किया।

1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की नायिका, झांसी की रानी लक्ष्मी बाई ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी तलवार उठाई। अपने छोटे से राज्य की रक्षा और देश की आजादी के लिए उन्होंने अभूतपूर्व साहस दिखाया। रानी ने अपने बेटे को पीठ पर बांधकर युद्ध लड़ा, जो नारी शक्ति का प्रतीक बन गया। उनकी वीरता की गूंज 15 अगस्त 1947 को आजादी के उत्सव में भी सुनाई दी।

₹तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा₹ - नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यह नारा हर भारतीय के दिल में गूंजता है। उनकी आजाद हिंद फौज ने ब्रिटिश शासन को सशस्त्र चुनौती दी। 1943 में नेताजी ने सिंगापुर में आजाद हिंद सरकार की स्थापना की और ₹दिल्ली चलो₹ का आह्वान किया। उनकी यह लड़ाई 15 अगस्त 1947 को आजादी के रूप में परिणत हुई।

15 अगस्त की कहानी केवल बड़े नेताओं की नहीं, बल्कि उन लाखों आम भारतीयों की भी है, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। चाहे वह लाला लाजपत राय हों जिन्होंने साइमन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया, या फिर गुमनाम किसान, मजदूर और महिलाएं, जिन्होंने आंदोलनों में हिस्सा लिया। इन सभी के छोटे-छोटे प्रयासों ने मिलकर भारत को आजादी दिलाई।

15 अगस्त 1947 को, भारत ने 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन से मुक्ति प्राप्त की। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिल्ली के लाल किले से तिरंगा फहराया और अपना प्रसिद्ध भाषण ₹ट्रिस्ट विद डेस्टिनी₹ दिया। यह दिन हमें याद दिलाता है कि आजादी केवल एक घटना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। हमें अपने देश को और मजबूत, समृद्ध और एकजुट बनाने के लिए प्रेरित करता है।

15 अगस्त हमें सिखाता है कि एकता, साहस और समर्पण के साथ हम अपने देश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। आइए, इस स्वतंत्रता दिवस पर हम अपने कर्तव्यों को याद करें और भारत को एक बेहतर राष्ट्र बनाने का संकल्प लें।

यह दिन केवल भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल था कि बिना हथियार उठाए, एक देश शांति और एकता से स्वतंत्र हो सकता है।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने संविधान निर्माण की ओर कदम बढ़ाया और 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। उसके बाद देश ने हर क्षेत्र में तरक्की की शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान और तकनीक में प्रगति हुई ₹रेलवे, सड़कों और संचार के माध्यमों का विकास हुआ ₹किसानों और गरीबों के लिए नई योजनाएँ बनीं। महिलाओं और पिछड़े वर्गों को अधिकार दिए गए। भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी गणराज्य के रूप में स्थापित किया। आज 15 अगस्त सिर्फ एक छुट्टी का दिन नहीं है बल्कि यह हमें हमारी जड़ों की याद दिलाता है।

झूलन महोत्सव में पधारे उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी

वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य पंचामृत से किया गिरिराज शिला का अभिषेक

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रमणरेती क्षेत्र स्थित श्रीजी सदन (फोगला आश्रम) में वृन्दावन रासलीला संस्थान व श्रीभगवान भजनाश्रम के संयुक्त तत्वावधान में श्रावण मास के अवसर पर चल रहे 19 दिवसीय 43वें झूलन महोत्सव के अंतर्गत प्रख्यात रासाचार्य स्वामी डॉ. देवकीनंदन शर्मा के निर्देशन में

गिरिराज पूजा, गोवर्धन लीला व 56 भोग दर्शन का आयोजन अत्यंत श्रद्धा व धूमधाम के साथ सम्पन्न हुआ।

महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी, श्रीभगवान भजनाश्रम के अध्यक्ष चांदबिहारी पाटोदिया, पूर्व पालिकाध्यक्ष पण्डित मुकेश गौतम, प्रमुख भाजपा नेता पण्डित योगेश द्विवेदी, प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी, एवं सैकड़ों भक्तों- श्रद्धालुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य श्रीगिरिराज शिला का दुग्धाभिषेक कर उनका पूजन-अर्चन किया।

मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने द्वापर युग में देवराज इंद्र के स्थान पर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाई थी। श्रीगिरिराज गोवर्धन कलयुग के प्रत्यक्ष देवता हैं, जो साक्षात रूप से ब्रजभूमि में विद्यमान होकर हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करते हैं। साथ ही जो भक्त सच्चे मन से गिरिराज गोवर्धन की भक्ति करता है, गिरिराज बाबा उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं।

प्रख्यात साहित्यकार डॉ. गोपाल चतुर्वेदी एवं पण्डित योगेश द्विवेदी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण ने गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा कर प्रकृति के महत्व को उजागर किया। प्रकृति के संरक्षण व संवर्द्धन से ही मानव जीवन स्वस्थ्य व समृद्ध हो सकता है। गिरिराज गोवर्धन साक्षात भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप होते हुए भी प्रकृति को अपनी भुजाओं से संजोए हुए हैं।

इस अवसर पर बिहारीलाल सर्राफ, प्रख्यात भागवताचार्य राधेश्याम शास्त्री, नरदेव चौधरी, भारत भूषण शर्मा, सौरभ शर्मा, भागवताचार्य गोपाल कृष्ण शर्मा, पण्डित श्याम सुंदर गोस्वामी, युवा साहित्यकार डॉ. राधाकांत शर्मा, राजकुमार पोद्दार आदि के अलावा विभिन्न क्षेत्रों के तमाम गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। रात्रि को संत, ब्रजवासी, वैष्णव सेवा (अन्नकूट प्रसादी) का आयोजन भी संपन्न हुआ।

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था महिला पदाधिकारियों ने भारतीय सेना के जवानों को राखी बांधकर मनाया रक्षाबंधन

एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू सदस्य दिव्यांशी जोशी के नेतृत्व में संस्था के माध्यम से रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर अपना घर परिवार छोड़कर रात दिन भारत देश की रक्षा कर रहे भारतीय सेना के जवानों को संस्था महिला पदाधिकारियों ने हल्द्वानी आर्मी कैंट में राखी बांधकर रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी

इस दौरान एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था अध्यक्ष योगेन्द्र कुमार साहू मार्गदर्शक पूर्णिमा रजवार ने संयुक्त रूप से कहा कि भारतीय सेना के जवानों का राष्ट्र हित कार्य यह दर्शाता है कि राष्ट्र की कुशलता से बड़ा कोई परिवार और सुख चैन नहीं होता है क्योंकि भारतीय सेना के जवान अपने स्वयं के घरों और परिवारजनों से हजारों किलोमीटर दूर रहकर भारत देश की सुरक्षा के लिए आस्थापूर्ण निष्ठापूर्ण श्रद्धापूर्ण दृढ़ संकल्प शक्ति के साथ सदैव तैनात होकर भारत देश की उन्नति प्रगति के लिए हमेशा भारतहित कार्य कर रहे है इसलिए हम सभी भारतीयों का यह कर्तव्य है की हमें अपने भारतीय सेना के जवानों के मनोबल बढ़ाने के लिए हर त्यौहार अपने प्यारे भारतीय सेना के जवानों के साथ मिलकर मनाना चाहिए जिससे उन्हें कभी भी घर परिवार की कमी महसूस न हो सके क्योंकि भारतीय सेना के जवान हजारों फुट की ऊंचाई पर अपनी हड्डियाँ गलाकर दुश्मनों की हर हरकत पर पैनी निगाह रखते हुए दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देकर दुश्मनों को संभलने का मौका भी नहीं देते है तब जाकर हम अपने घरों में सुरक्षित रहते है और तब हम अपने सारे त्योहारों को हर्ष उल्लास पूरी खुशी के साथ भयमुक्त होकर मना पाते है इसलिए हमें अपनी भारतीय सेना के प्रति सच्ची निष्ठा आस्था रखते हुए भक्ति भाव प्रकट कर सारे त्यौहार अपनी भारतीय सेना के साथ मिलकर मनाने चाहिए जिससे हमारे भारत देश की अटूट स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने में हम भारतवासियों के साथ भारतीय सेना को और मजबूती मिलेगी

इस दौरान जवानों को राखी बांधने में एक समाज श्रेष्ठ समाज संस्था सदस्य पूर्णिमा रजवार योगिता बनोला मीना जोशी दिव्यांशी जोशी पूजा जोशी रिंकी गुप्ता अंशिका साहू धर्मा बिष्ट रेनू कांडपाल पूनम गुप्ता जया जोशी दीपा रावत एकता कुमारी प्रीति गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे

इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था कोषाध्यक्ष बलराम हालदार मनीष साहू रोहतास प्रजापति सूरज कुम्हार दीपक कुमार मुकेश कुमार उपस्थित रहे।

भारत पर ट्रंप का टैरिफ वार- भारत का झुकने से इनकार- विश्व के दिग्गज़ देश भारतीय समर्थन को तैयार ?

दुनियाँ के सबसे ताकतवर देश से भारत दो-दो हाथ करने को तैयार -पीएम की हुंकार- व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई कीमत चुकाने पड़ेगी तो मैं तैयार हूं- देश को पीएम पर नाज़ है!-एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तर पर पिछले कुछ दिनों से अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनियाँ में अपने टैरिफ़ की हुंकार भर रहे हैं, जिसको वह एक दबाव क़े अस्त्र के रूप में उपयोग कर, सभी देशों से अपने ढंग से अपनी शर्तों पर समझौता करवा कर उन्हें टैरिफ में छूट दे रहे हैं। जबकि जिस देश में अमेरिका का काम अड़ा हुआ है या कुछ जरूरी आपूर्ति के रूप में प्राप्त हो रहा है तो उसे वह छोड़ रहे हैं।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र ऐसा मानता हूं कि अनेक देश उनके टैरिफ दबाव के कारण समझौते पर राजी हो गए हैं, परंतु भारत रूस से रक्षा उपकरण खरीदने तथा पशुपालन डेयरी फार्म, किसान व मछली उद्यम क्षेत्र सहित कुछ मुद्दों पर मुक्त व्यापार समझौता नहीं करने पर अड़ा हुआ है, जिसके कारण बात बहुत भयंकर हद तक बिगड़ गई है। दो दिन पूर्व 50 पेर्सेंट टैरिफ की घोषणा के बाद, अब 8 जुलाई 2025 को ट्रंप ने भारत के साथ ट्रेड पर कोई मीटिंग या बातचीत नहीं करने की घोषणा की है, यानें अब अमेरिका से आने वाला अधिकारियों का डेलिगेशन नहीं आएगा तथा अब भारत अमेरिका के साथ दो-दो हाथ करने को तैयार बैठा है, जिसपर ट्रंप सहित पूरा विश्व हैरान है कि, भारत ने इतने प्रभावशाली देश को तगड़ा जवाब कैसे दे दिया, भारत के पीछे उसके साथ कौन आकर खड़ा हो गया है? इत्यादि अनेक सवाल उठ गए हैं। बता दें 8 अगस्त 2025 को ही भारतीय पीएम ने रूस के राष्ट्रपति के साथ टेलीफोन पर वार्ता की, व रूसी राष्ट्रपति की शीघ्र ही भारत आने की संभावना है, तथा चीन ब्राजील इजरायल ईरान से भी भारत का समर्थन करने के इंडिकेशन प्राप्त हो रहे हैं। संभावना है कि भारतीय पीएम 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेने व चीन रूस ब्राजील इत्यादि देशों से नतीजात्मक वार्ता जरूर होगी व रूस चीन भारत का ट्रायंगल बन सकता है, जो अमेरिका के लिए मुसीबतों का द्वार खोल सकता है, तो फिर निश्चित रूप से नोबेल शांति पुरस्कार पाने की चाहत को झटका लग सकता है। उधर पाक जनरल का अमेरिका के निरंतरण पर कुछ हफ्तों में दूसरी बार दौरा कर रहे हैं।इस बीच ट्रंप ने और अधिक टैरिफ बढ़ाने और अनेक पाबंदियां लगाने का इशारा दे दिया है। बता दे उन्हें संसद से 500 पेर्सेंट तक टेरिफ लगाए जाने वाला बिल पास होने की संभावना है।चूँकि भारत पर ट्रंप का टैरिफ वार, भारत क़ा झुकाने से इनकार, विश्व के दिग्गज देश भारतीय समर्थन को तैयार ?इसलिए आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी के सहयोग से इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, ट्रंप के टैरिफ पीड़ित देशों का समूह अगर एकजुट हुए तो ट्रंप की मुश्किलें बहुत अधिक बढ़ेगी ?

साथियों बात अगर हम टैरिफ मुद्दे पर भारत अमेरिका की तेजी से बढ़ती तकरार की करें तो, एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत से आयातित सामान पर टैक्स 25 से बढ़ाकर 50 फीसदी कर दिया है तो वहीं भारत ने ट्रंप के इस फैसले को पूरी तरह अनुचित ,अन्यायपूर्ण और असंगत करार दिया, वहीं भारत क़े पीएम ने भी बिना नाम लिये अमेरिका को कड़ा संदेश दिया है।भारत के खिलाफ ट्रम्प के टैरीफ वार ने देश के 146 करोड़ लोगों को एकजुट कर दिया है। भारत ने अमेरिका को एक दोस्त मानते हुए बराबरी के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश की। लेकिन ट्रम्प भारत से व्यक्तिगत और व्यापारिक फायदे उठाना चाहते थे। आज हमारे देश में करीब 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर है, करीब 3 करोड़ लोग मछलीपालन से जुड़े हुए है, जबकि 8 करोड़ परिवार ऐसे है जिनके पास गाय-भैंस है।आज इन सभी लोगों के हितों को बचाने केलिए पीएम लड़ रहे हैं।

साथियों बात अगर हम टैरिफ मुद्दे पर अमेरिका से बढ़ते तकरार, बिगड़ते रिश्तों से भारत को विश्व के अनेक दिग्गज नेताओं का साथ होने की करें तो, टैरिफ वॉर पर अब चीन रूस ब्राजील इजरायल ईरान भारत के पक्ष में बात कर रहा है। भारत में चीन के राजदूत ने एक सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते लिखा है - गिव द बुली एन इंच, he विल टेक ए माइल, इसका सीधा मतलब- ये है कि अगर किसी धमकी देने वाले को आप ज़रा सी छूट देते हैं तो वो उसका पूरा फायदा उठाकर आपसे और ज्यादा हथियाने की कोशिश करेगा। इसे संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र का उल्लंघन बताया है।

साथियों बात अगर हम भारत अमेरिका के बीच बढ़ते तकरार को पांच मुद्दों में समझने की करें तो (1) ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत के साथ व्यापार घाटा और अमेरिकी वस्तुओं की बाज़ार पहुंच पर बाधाओं के कारण उन्हें भारत पर ज्यादा टैरिफ लगाना पड़ा है (2) पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष विराम का दावा नहीं मानना- ट्रंप लगातार यह दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष को रुकवाया, वह ये दावा कम से कम 25 बार तो कर ही चुके हैं लेकिन भारत इन दावों को बार-बार खारिज करता रहा है।(3)ब्रिक्स को लेकर भी हैं खफा- ब्रिक्स लेकर भी भारत को निशाना बना रहे हैं क्योंकि ब्रिक्स देशों की नीतियां अमेरिकी डॉलर की वैश्विक स्थिति को चुनौती देती हैं। ब्रिक्स समूह (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका और हाल में जुड़े कुछ अन्य देश) वैश्विक जीडीपी का 40% तक योगदान करता है. इन देशों का आपसी व्यापार बढ़ना. डॉलर की जगह अन्य करेंसी विकल्पों की चर्चा ट्रंप को असहज कर रही है, (4) यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद भारत ने रूसी तेल का आयात काफी बढ़ाया है. अब भारत अपनी कुल जरूरतों का करीब 36-40% तेल रूस से आयात करता है. इससे भारत को रियायती दरों पर तेल मिलता है. महंगाई नियंत्रित रहती है, लेकिन पश्चिमी देशों खासकर

अमेरिका में इसकी आलोचना हुई, ट्रंप का मानना है कि भारत रूस से भारी मात्रा में तेल खरीदकर 'रूसी वॉर मशीन' को मदद कर रहा है, जिससे यूक्रेन में भयंकर युद्ध चला आ रहा है।

साथियों बात अगर हम भारतीय पीएम के व्यक्तिगत नुकसान को भी सहन करने के बयान का विश्लेषण करें तो, उन्होंने अमेरिका के टैरिफ के मुद्दे पर कहा है कि व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई कीमत चुकानी पड़ेगी तो मैं तैयार हूं-तो यह एक राजनीतिक और कूटनीतिक बयान है, जिसमें ₹व्यक्तिगत कीमत₹ का मतलब सीधे पैसे से नहीं, बल्कि राजनीतिक, कूटनीतिक, और छवि संबंधी नुकसान से होता है। उनके लिए ऐसी संभावित व्यक्तिगत कीमतें इस प्रकार हो सकती हैं:(अ) राजनीतिक प्रतिष्ठा पर असर (1) घरेलू राजनीति में आलोचना कि अमेरिका से टकराव के कारण व्यापार, निवेश या तकनीकी सहयोग में कमी आई। (2) विपक्ष का यह आरोप कि प्रधानमंत्री की नीतियों से देश की अर्थव्यवस्था या कूटनीतिक रिश्ते बिगड़े। (3) अंतरराष्ट्रीय मंचों पर "कठोर" या "जिद्दी" छवि बनने से लचीले नेता की छवि कमजोर होना।(ब) कूटनीतिक पूंजी की हानिः-(1) अमेरिका जैसे रणनीतिक साझेदार के साथ व्यक्तिगत संबंधों में ठंडापन आना। (2) अन्य पश्चिमी देशों में भारत के लिए लॉबिंग क्षमता घटना, क्योंकि अक्सर नेता-से-नेता भरोसा महत्वपूर्ण होता है।(3) अंतरराष्ट्रीय वार्ताओं में समर्थन कम मिलना (जैसे जलवायु परिवर्तन, यूएनएससी स्थायी सदस्यता आदि) (स) आर्थिक विकास एजेंडे पर दबाव (1) यदि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत के निर्यात पर नकारात्मक असर पड़ा, तो विकास, रोजगार और विदेशी निवेश के लक्ष्यों पर चोट लगना-इसका राजनीतिक दोष सीधे प्रधानमंत्री पर आना।(2) वैश्विक कंपनियों का निवेश निर्णय टलना या शिफ्ट होना, जिससे ₹मेक इन इंडिया₹ जैसी योजनाओं की गति प्रभावित होना। (क) व्यक्तिगत छवि का अंतरराष्ट्रीय मीडिया में गिरनाः- (1) विदेशी मीडिया में ₹अमेरिका से रिश्ते खराब करने वाले नेता₹ के रूप में चित्रण।(2) निवेशकों और वैश्विक राजनैतिक विश्लेषकों के बीच विश्वास में कमी (3) "वैश्विक डीलमेकर" की ब्रांडिंग पर असर। (5) जी-20 और वैश्विक नेतृत्व भूमिकाओं पर असरः-(1) भविष्य में बड़े मंचों पर भारत की मेजबानी या नेतृत्व भूमिका में अमेरिका का कम समर्थन। (2) वैश्विक मुद्दों पर भारत की आवाज़ कमज़ोर पड़ना, जिससे मोदी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा घट सकती है। (6) चुनावी रणनीति पर प्रभावः-(1) यदि टैरिफ वार के कारण महंगाई, बेरोज़गारी या व्यापार घाटा बढ़ा, तो विपक्ष इन मुद्दों को चुनावी हथियार बना सकता है। (2) ग्रामीण और औद्योगिक क्षेत्रों के वोटरों में असंतोष-खासकर यदि कृषि, डेयरी या टेक सेक्टर प्रभावित हों। (फ़) व्यक्तिगत रिश्तों में ठंडापनः-(1) डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के साथ जो ₹दोस्ती₹ वाली राजनीतिक तस्वीरें बनीं, वे कमजोर होना (2) भविष्य की निजी मुलाकातों या त्वरित फोन डिप्लोमेसी में कठिनाई बढ़ना।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत पर ट्रंप का टैरिफ वार- भारत का झुकने से इनकार- विश्व के दिग्गज़ देश भारतीय समर्थन को तैयार ?ट्रंप क़े खिलाफ़ टैरिफ़ से पीड़ित देशों क़े एकजुट होनें से ट्रंप की मुश्किलें बनेगी ?दुनियाँ के सबसे ताकतवर देश से भारत दो-दो हाथ करने को तैयार-पीएम की हुंकार- व्यक्तिगत रूप से मुझे कोई कीमत चुकाने पड़ेगी तो मैं तैयार हूं- देश को पीएम पर नाज़ है!

रोहित शर्मा ने खरीदी दूसरी लैम्बॉघिनी Urus, कीमत जानकर उड़ जाएगा होश

भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने Lamborghini Urus का अपडेटेड SE वर्जन खरीदा है। उन्होंने पहले वाली Urus को Dream11 कॉन्टेस्ट के विजेता को दे दिया था। नई Urus SE में 4.0-लीटर का ट्विन-टर्बो V8 इंजन है जो 620hp की पावर देता है। यह इलेक्ट्रिक मोड में 60 किमी तक चल सकती है और 0-100km/h की रफ्तार 3.4 सेकेंड में पकड़ सकती है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.57 करोड़ रुपये है।

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा ने एक बार फिर से Lamborghini Urus को खरीदा है। इस बार रोहित शर्मा ने इसका अपडेटेड SE वर्जन को खरीदा है। रोहित ने इसे फिर से इसलिए खरीदा है, क्योंकि उन्होंने अपने पुराने Urus को Dream11 फैंटेसी क्रिकेट कॉन्टेस्ट के विजेता को देने का ऐलान किया था। जिसे उन्होंने विजेता को शौप दिया था।

सोशल मीडिया पर शेयर हुए एक वीडियो में Lamborghini मुंबई डीलरशिप को रोहित शर्मा को नई Urus SE डिलीवर करते हुए देखा गया। वीडियो में SUV का नया ऑरेंज शेड (Arancio Argos) नजर आ रहा है, जो उनके पहले वाली ब्लू Urus से अलग है। हालांकि, डिलीवरी के समय रोहित की तस्वीरें सामने नहीं आई हैं।

डिजाइन और फीचर्स

Lamborghini Urus SE में पुराने मॉडल की तुलना में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इसमें नया LED मैट्रिक्स हेडलाइट डिजाइन है, जो पहले के Y-मोटिफ से अलग है। फ्रंट बंपर और बड़ा ग्रिल इसे ज्यादा आक्रामक लुक देता है। इसमें दिए गए 23-इंच के अलॉय व्हील्स इसके स्पोर्टी लुक को बढ़ाने का काम करता है।

पावरट्रेन और परफॉर्मेंस

नई Lamborghini Urus SE में 4.0-लीटर, ट्विन-टर्बो V8 इंजन का इस्तेमाल किया गया है। इसका इंजन 620hp की पावर और 800Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 25.9kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक वाले प्लग-इन हाइब्रिड सिस्टम भी दिया गया है, जिसकी वजह से कार का इंजन कुल 800hp की पावर और 950Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

यह SUV सिर्फ इलेक्ट्रिक मोड में 60 किमी तक चल सकती है और 130km/h तक की स्पीड पर EV मोड में काम करती है। 0-100km/h की रफ्तार पकड़ने में इसे सिर्फ 3.4 सेकेंड लगते हैं और इसकी टॉप स्पीड 312km/h है।

Lamborghini Urus SE के कीमत की बात करें, तो जिस मॉडल को रोहित शर्मा ने खरीदा है, उसकी एक्स-शोरूम कीमत 4.57 करोड़ रुपये है।

नई हीरो ग्लैमर 125 इस फेस्टिव सीजन में होगी लॉन्च, मिलेगा क्रूज कंट्रोल और नए फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही नई Glamour 125 लॉन्च करने की तैयारी में है जिसे फेस्टिव सीजन में पेश किया जा सकता है। हाल ही में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट की गई इस बाइक में कई अपडेट देखने को मिल सकते हैं। इसमें नया स्विचगियर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल बटन जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। LCD स्क्रीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग पोर्ट भी मिलने की संभावना है।

नई दिल्ली। हीरो मॉटोकॉर्प जल्द अपनी नई Glamour 125 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इसे फेस्टिव सीजन में इसे लॉन्च किया जा सकता है। हाल ही में इस बाइक को टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया था। इसके टेस्टिंग मॉडल में कई अपडेट देखने के लिए मिल सकता है। आइए विस्तार में जानते हैं कि नई Glamour 125 को किन खास फीचर्स के साथ लॉन्च किया जा सकता है।

टेस्टिंग मॉडल में क्या दिखा था?

टेस्टिंग मॉडल में एक छोटा अपग्रेड नहीं, बल्कि Glamour का नेक्स्ट-जेनरेशन मॉडल हो सकता है। बाइक को पूरी तरह से कवर की गई थी, लेकिन फिर भी कुछ खास डिटेल्स देखने के लिए मिल सकती है। इसमें नया स्विचगियर और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है। यह अपने सेगमेंट की पहली बाइक हो सकती है, जिसमें क्रूज कंट्रोल बटन जिया जा सकता है। यह टॉगल बटन राइट साइड स्विचगियर दिया जा सकता है, जिसे इग्निशन बटन के नीचे लगाया जा सकता है। इसमें लेफ्ट साइड स्विचगियर भी दिया जा सकता है और इसमें LCD स्क्रीन को नेविगेट करने के लिए बटन भी दिए जा सकते हैं।

मिल सकते हैं ये भी फीचर्स

इसमें मिलने वाली LCD स्क्रीन Karizma XMR 210 और Xtreme 250R जैसी हो सकती है। इस स्क्रीन नें स्क्रीन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दी जा सकती है, जो टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, SMS और कॉल अलर्ट जैसी सुविधाएं देगा। इसके साथ ही USB चार्जिंग पोर्ट भी स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर दिया जा सकता है। इसके बॉडीवर्क में बड़े बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं।

हार्डवेयर के मामले में बदलाव की उम्मीद कम है, यानी इंजन और सस्पेंशन सेटअप लगभग वही रह सकता है। नई Glamour 125 मौजूदा मॉडल को रिप्लेस करेगी।

12 अगस्त को नई येजदी रॉडस्टर भारत में होगी लॉन्च, डिजाइन समेत इंजन में होंगे बड़े बदलाव

येज्दी मोटरसाइकिल्स 12 अगस्त 2025 को अपनी नई मोटरसाइकिल येज्दी रोडस्टर लॉन्च करेगी। टीजर में LED हेडलाइट और टेललैंप की झलक दिखती है। 2025 येज्दी रोडस्टर में नया LED हेडलैंप और बेहतर बिल्ड क्वालिटी मिल सकती है। यह दो वेरिएंट में आ सकती है जिसमें क्रूजर स्टाइल और बॉबर वर्जन शामिल हैं। इसमें 334cc का इंजन होगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 2.10 लाख रुपये हो सकती है।

नई दिल्ली। येज्दी मोटरसाइकिल्स ने अपनी जल्द लॉन्च होने वाली मोटरसाइकिल का एक और टीजर जारी किया है। इस टीजर में कंपनी ने इसकी लॉन्चिंग तारीख का भी एलान किया है। येज्दी अपनी इस नई मोटरसाइकिल को 12 अगस्त 2025 को भारत में लॉन्च करने वाली है। इस टीजर में बाइक के पिछले हिस्से को दिखाया गया है, जिसमें नई LED हेडलाइट, टेललैंप और इंडिकेटर्स की झलक देखने को मिली है। कंपनी की नई बाइक Yezdi Roadster होने वाली है। आइए जानते हैं कि नई येज्दी रोडस्टर को किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

डिजाइन और फीचर्स में बड़े अपडेट

2025 Yezdi Roadster में नया LED हेडलैंप, टेललाइट और इंडिकेटर्स के साथ एक नई कलर पैलेट दी जा सकती है। जैसा कि हाल ही में आई येज्दी की आई मोटरसाइकिल में देखने के लिए मिल चुका है, वैसे ही रोडस्टर में भी बिल्ड क्वालिटी में सुधार देखने को मिल सकता है।

नया बॉबर वेरिएंट भी हो सकता है लॉन्च

2025 Yezdi Roadster को दो वेरिएंट में लाया जा सकता है। इसका एक वेरिएंट क्रूजर स्टाइल और दूसरा नया बॉबर वर्जन हो सकता है। इसके बॉबर वेरिएंट में सिंगल-सीट डिजाइन, छोटा रियर फेंडर और क्लासिक ट्विन-एग्जॉस्ट सेटअप देखने के लिए मिल सकता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

2025 Yezdi Roadster मे अपडेटेड Alpha 2 इंजन दिया जाएगा, जो नई Yezdi Adventure में भी इस्तेमाल हो रहा है। इसमें 334cc लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन देखने के लिए मिलेगा, जो 29.6 bhp की पावर और 29.9 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसके इंजन को 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जा सकता है। इसे आरामदायक क्रूजर राइडिंग कैरेक्टर के अनुसार ट्यून किया जा सकता है। इसमें फ्रंट में टेलिस्कोपिक फोर्क्स और रियर में ट्विन शॉक्स दिए जा सकते हैं, जबकि ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में डुअल डिस्क और रियर में सिंगल डिस्क सेटअप मिल सकता है।

कितनी है कीमत?

हाल में मिलने वाली Yezdi Roadster की एक्स-शोरूम कीमत 2.10 लाख रुपये से शुरू होकर 2.19 लाख रुपये तक जाती है। इसे अपडेट मिलने के बाद कीमत में हल्का बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। भारत में इसका मुकाबला Honda CB350, Royal Enfield Meteor 350 और Triumph Speed 400 से देखने के लिए मिल सकता है।

वीएलएफ मॉब्स्टर स्कूटर 25 सितंबर को भारत में होगा लॉन्च, मिलेगा दमदार डिजाइन और प्रीमियम फीचर्स

इटैलियन कंपनी Motohaus भारतीय बाजार में अपना नया VLF Mobster स्कूटर लॉन्च करने जा रही है। यह 25 सितंबर को पेश किया जाएगा। दमदार डिजाइन वाले इस स्कूटर में प्रीमियम फीचर्स और हार्डवेयर दिए गए हैं। इसमें डिस्क ब्रेक टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और 12-इंच एलॉय व्हील्स मिलेंगे। यह 125cc या 180cc इंजन के साथ आ सकता है। स्कूटर में 5-इंच का डिजिटल TFT डिस्प्ले भी दिया गया है।

नई दिल्ली। इटैलियन कंपनी Motohaus ने घोषणा की है कि उनका नया VLF Mobster स्कूटर भारतीय बाजार में लॉन्च करने की घोषणा की है। कंपनी इसे भारतीय बाजार में 25 सितंबर को लॉन्च करने वाली है। यह कंपनी का भारत में दूसरा प्रोडक्ट होगा, जो टेनिस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बाद पेश किया जा रहा है। यह कंपनी का देश में पहला पेट्रोल स्कूटर होने वाला है। आइए जानते हैं कि यह स्कूटर किन बेहतरीन फीचर्स के साथ आने वाला है?

दमदार और मस्कुलर डिजाइन

VLF Mobster स्कूटर का डिजाइन भारतीय बाजार में मिलने वाले दूरसे स्कूटरों से काफी अलग और बोल्ड है। इसमें फ्रंट पैनल पर ट्विन-हेडलैंप सेटअप, चौड़ा हैंडलबार और यूनिक साइड पैनल भी दिया गया है, जो इसे और भी दमदार लुक देने का काम करता है। इसमें सिंगल-पीस सीट डिजाइन और स्ट्रीट बाइक जैसे हैंडलबार इसकी स्पोर्टी अपील को और बढ़ाता है।

प्रीमियम फीचर्स और हार्डवेयर

VLF Mobster स्कूटर में कई प्रीमियम कंपोनेंट्स के साथ लेकर आया गया है। इसमें डिस्क ब्रेक सिस्टम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर डुअल शॉक एब्जॉर्बर्स और 12-इंच एलॉय व्हील्स देखने के लिए मिलेंगे। इसमें आगे की तरफ 120-सेक्शन और पीछे 130-सेक्शन टायर दिए जा सकते है, जो बेहतर ग्रिप और स्टेबिलिटी देने का काम करेंगे।

मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फीचर्स

VLF Mobster स्कूटर में 5-इंच का फुली डिजिटल कलर TFT डिस्प्ले मिल सकता है, जो मोबाइल स्क्रीन मिररिंग सपोर्ट करता है। इसमें USB चार्जिंग पोर्ट, स्विचेबल डुअल-चैनल ABS और लाइव डैशकैम फंक्शन भी दिया जा सकता है।

पावरफुल होगा इंजन

VLF Mobster स्कूटर मे 125cc का इंजन दिया जाएगा या फिर 180cc का इंजन अभी तक इसकी पूरी जानकारी नहीं दी गई है। अगर इसमें 125cc का इंजन दिया जाता है, तो यह 12 bhp की पावर और 11.7 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। अगर 180cc वाला इंजन मिलता है, तो 18 bhp की पावर और 15.7 Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। इसे ग्रे, व्हाइट, रेड और येलो जैसे कलर ऑप्शन दिया जा सकता है।

निसान मैग्नाइट पर 80 हजार की छूट; 24km का माइलेज, सनरूफ सहित खास फीचर्स से लैस

निसान इंडिया अपनी सब 4-मीटर SUV Nissan Magnite के लिए अगस्त में डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है जिसमें कैश डिस्काउंट एक्सचेंज बोनस और फाइनेंसिंग स्कीम शामिल हैं। कुरो एडिशन पर कोई छूट नहीं है। दिल्ली-NCR में ग्राहकों के लिए एक्सचेंज बोनस और दक्षिण भारतीय राज्यों में फाइनेंस स्कीम उपलब्ध है। Visia और Acenta वेरिएंट पर 10000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है।

नई दिल्ली। निसान इंडिया ने हाल ही में अपनी सब 4-मीटर SUV Nissan Magnite का ऑल-ब्लैक कुरो एडिशन को लॉन्च किया है। इस कुरो एडिशन की एक्स-शोरूम कीमत 8.31 लाख रुपये से लेकर 10.87 लाख रुपये तक है। अब कंपनी ने अगस्त 2025 में इसके वेरिएंट के हिसाब डिस्काउंट ऑफर लेकर आई है। इन ऑफर्स में कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस, कॉरपोरेट डिस्काउंट और खास फाइनेंसिंग स्कीम तक शामिल है। कुरो एडिशन पर किसी तरह का डिस्काउंट ऑफर नहीं दिया जा रहा है। आइए जानते है कि Nissan Magnite पर मिलने वाले डिस्काउंट ऑफर के बारे में।

Nissan Magnite पर डिस्काउंट ऑफर

ऑफ़र्सराशि

कैश और एक्सेसरीज डिस्काउंट 20,000
एक्सचेंज बोनस (Datsun/Nissan कारें) 55,000
एक्सचेंज बोनस (अन्य ब्रांड की कारें) 35,000
एंड ऑफ लाइफ एक्सचेंज बोनस 51,000
कॉरपोरेट डिस्काउंट 5,000
कुल लाभ 80,000

दिल्ली-NCR के ग्राहकों के लिए एंड ऑफ लाइफ एक्सचेंज बोनस की सुविधा मिल रही है।

केरल समेत दक्षिण भारतीय राज्यों में centa, N-Connecta, Tekna और Tekna Plus ट्रिम पर 6.99% ब्याज दर पर फाइनेंस स्कीम दी जा रही है।

Visia और Visia Plus वेरिएंट के मैनुअल और एएमटी दोनों पर कैश डिस्काउंट 10,000 रुपये दिया जा रहा है।

लोअर-स्पेक Acenta वेरिएंट पर भी 10,000 रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है।

N-Connecta, Tekna और Tekna Plus वेरिएंट पर पहले बताए गए सभी डिस्काउंट मिल रहे हैं।

Nissan Magnite की एक्स-शोरूम कीमत 6.14 लाख से लेकर 11.76 लाख रुपये के बीच हैं।

Nissan Magnite के फीचर्स

इसे 1.0-लीटर NA पेट्रोल या 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ पेश किया जाता है। इसका 1.0-लीटर NA पेट्रोल वाला इंजन 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसका 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल वाला इंजन 99 bhp की पावर और 160 Nm टॉर्क जनरेट करता है।

इसमें 360-डिग्री कैमरा, वायरलेस फोन मिररिंग, ड्राइवर की सीट के लिए ऊंचाई समायोजन, पावर्ड मिरर, HEPA एयर फिल्टर, LED हेडलैंप और LED DRLs जैसे फीचर्स मिलते हैं।

इसमें पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए VDC, ESC, TPMS, EBS के साथ ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, हिल स्टार्ट असिस्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट, रेनफोर्ड बॉडी स्ट्रक्चर, डोर प्रेशर सेंसर और ग्रेविटेशनल सेंसर, ड्राइवर सीट बेल्ट लैप प्रेटेनस्रनर, 6 एयर बैग्स, सभी सीट के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, ISO FIX चाइल्ड सिट एन्चोरेजेस, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, ESS जैसी सुविधाएं दी जाती है।

डिस्क्लेमर- एक्सचेंज बोनस की राशि चुने गए वेरिएंट और आपके क्षेत्र पर निर्भर करेगी। सही ऑफर जानने के लिए नजदीकी निसान डीलरशिप से संपर्क करना बेहतर रहेगा। ये सभी ऑफर 31 अगस्त 2025 तक मान्य हैं।

वैज्ञानिक सुधार के 78 साल: स्वतंत्रता के बाद से विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार में देश की उल्लेखनीय यात्रा

विजय गर्ग

संस्थागत ढांचा: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और एक कुशल कार्यबल बनाने के लिए की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया था, इसके बाद 1957 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आधार बनाया।

विजय गर्ग

स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से, भारत ने वैज्ञानिक सुधार और प्रगति की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की है, जो विभिन्न वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में एक वैश्विक खिलाड़ी के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करने वाले राष्ट्र से बदल रही है। 78 वर्षों की यात्रा, आत्मनिर्भरता, रणनीतिक नीति निर्णयों और मजबूत संस्थानों की स्थापना के लिए एक मजबूत प्रतिबद्धता की विशेषता रही है। प्रारंभिक नींव और दृष्टि (1947-1970) स्वतंत्रता के बाद के युग को राष्ट्र-निर्माण के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दोहन के लिए एक दृष्टि द्वारा चिह्नित किया गया था। पहले प्रधान मंत्री, जवाहरलाल नेहरू, एक ₹वैज्ञानिक स्वभाव₹ के एक मजबूत प्रस्तावक थे और उन्होंने भारत के वैज्ञानिक पारिस्थितिकी तंत्र के मूलभूत स्तंभों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

संस्थागत ढांचा: वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) जैसे प्रमुख संस्थानों की स्थापना अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने और एक कुशल कार्यबल बनाने के लिए की गई थी। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन 1948 में किया गया था, इसके बाद 1957 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने भारत के परमाणु कार्यक्रम के लिए आधार बनाया।

विज्ञान नीति संकल्प 1958: यह ऐतिहासिक संकल्प अपने सभी रूपों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा थी। इसने राष्ट्र की प्रगति के लिए शुद्ध, लागू और शैक्षिक अनुसंधान के महत्व पर जोर दिया।

हरित क्रांति: 1960 और 70 के दशक में, भारत को भोजन की गंभीर कमी का सामना करना पड़ा। कृषि विज्ञान में एक स्मारकीय उपलब्धि हरित क्रांति ने देश की खाद्य सुरक्षा को बदल दिया। उच्च उपज वाली फसल किस्मों, आधुनिक कृषि तकनीकों और बेहतर सिंचाई की शुरुआत करके, भारत खाद्य-घाटे से खाद्य-अधिशेष राष्ट्र में स्थानांतरित करने में

सक्षम था।

अंतरिक्ष कार्यक्रम उत्पत्ति: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का गठन 1969 में हुआ था, और 1975 में भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण ने अंतरिक्ष युग में देश के प्रवेश को चिह्नित किया था। रणनीतिक विकास और स्व-रिलायंस (1980-2000) इस अवधि में भारत ने अपनी वैज्ञानिक क्षमताओं को मजबूत किया और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी विकास पर ध्यान केंद्रित किया।

परमाणु और रक्षा क्षमताएं: भारत ने 1974 में परमाणु प्रौद्योगिकी की अपनी महारत का प्रदर्शन करते हुए अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, ₹मुस्कुराते हुए बुद्ध₹। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम 1983 में शुरू किया गया था, जिससे पृथ्वी और अग्नि जैसी स्वदेशी मिसाइलों का विकास हुआ।

जैव प्रौद्योगिकी और आईटी: जैव प्रौद्योगिकी विभाग की स्थापना 1986 में इस उभरते क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इसके साथ ही, भारत का सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र पनपने लगा, आर्थिक विकास का एक प्रमुख इंजन बन गया।

अंतरिक्ष अन्वेषण मील के पत्थर: भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने अपने स्वयं के लॉन्च वाहनों (एसएलवी -3, पीएसएलवी और जीएसएलवी) के विकास और संचार और दूरस्थ संवेदन उपग्रहों के प्रक्षेपण सहित महत्वपूर्ण मील के पत्थर हासिल किए, जो लाखों लोगों के लिए सेवाएं लाए। ग्लोबल स्टेचर एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हाल के दशकों में, भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को मजबूत किया है, अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों के साथ दुनिया भर में मान्यता प्राप्त की है।

चंद्र और ग्रहों की खोज: चंद्रमा के लिए चंद्रयान मिशन, जिसमें 2023 में चंद्र दक्षिण ध्रुव के पास चंद्रयान -3 की सफल नरम लैंडिंग शामिल है, भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं का एक वसीयतनामा रहा है। मार्स ऑर्बिटर मिशन (मंगलयान) ने 2013 में भारत को अपने पहले प्रयास पर मंगल की कक्षा में पहुंचने वाला पहला देश बना दिया था।

हेल्थकेयर एंड फार्मास्यूटिकल्स: भारत ₹दुनिया की फार्मेसी₹ बन गया है, जो सस्ती और प्रभावी दवाओं और टीकों का उत्पादन करता है। कोवड-19 महामारी के दौरान कोवाक्सिन जैसे स्वदेशी टीकों के विकास ने जैव प्रौद्योगिकी और सार्वजनिक स्वास्थ्य में देश की प्रगति पर प्रकाश डाला।

भविष्य पर ध्यान दें: सरकार अर्धचालक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी भविष्य की प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है। विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2013 जैसी नीतियों का उद्देश्य आर एंड डी में सार्वजनिक और निजी निवेश को बढ़ाना और राष्ट्रीय चुनौतियों को हल करने के लिए एक मिशन-मोड दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है।

सेवानिवृत्त प्राचार्य शैक्षिक स्तंभकार प्रख्यात शिक्षाविद्,

सभ्यताओं को बनाने मिटाने का खेल

शिवानन्द मिश्रा

आपने हमेशा सुना होगा — "चीन की दीवार" — जिसे कहा जाता है कि चीनियों ने टार्टेरियन साम्राज्य से बचने के लिए बनाई और जिसका निर्माण करीब 1400 वर्षों तक चला।

दीवार की संरचना बिल्कुल वैसी है जैसे अक्षय कुमार की केसरी फिल्म में छत की दीवार अफगानों की ओर थी और पीछे से सैनिक गोली चला रहे थे।

अगर ये सचमुच चीन ने बनाई होती तो उसकी दीवार का रुख टार्टेरियन साम्राज्य की तरफ होना चाहिए था लेकिन असल में ये उल्टा है — दीवार का मुँह चीन की ओर है।

असलियत शायद ये है कि ये दीवार टार्टेरियन साम्राज्य की है जो उन्होंने चीन से बचाव के लिए बनाई होगी। 1700 साल पुरानी ये रचना उस समय की अति आधुनिक प्राचीन सभ्यता की निशानी हो सकती है।

दुनिया में जितनी भी अत्याधुनिक सभ्यताएं आईं, उनका इतिहास मिटा दिया गया। टार्टेरियन साम्राज्य के बारे में रिसर्च करने पर कोई ठोस डेटा नहीं मिलेगा।

कहा जाता है कि टार्टेरियन भूमि समुद्रविहीन थी लेकिन एक भयंकर कीचड़-सैलाब में सब दफन हो गया। आश्चर्य ये कि उस सभ्यता का एक भी ठोस अवशेष नहीं बचा — जो प्राकृतिक रूप से असंभव लगता है।

इस सभ्यता के ऊंचे-ऊंचे महलों के शिखरों में विद्युत उत्पादन के रहस्य थे। 1800 से 1930 तक अमेरिका और यूरोप में बनी कई इमारतें इसी डिज़ाइन पर थीं — जिन्हें बाद में बिना वजह गिरा दिया गया, और वह भी विश्व युद्ध से पहले ताकि कोई बहाना न बन सके।

असल नियम ये है — जहाँ भी प्राचीन काल की अत्याधुनिक तकनीक या वास्तुकला मिलती है, उसे तुरंत नष्ट कर दिया जाता है। लगता है कि उनके पास टाइम मशीन हो और वे इसे अपने फायदे के लिए गुप्त रखेंगे न कि सबको देंगे।

कई सभ्यताएं प्राकृतिक आपदा से नहीं बल्कि जानबूझकर मिटाई गईं। केवल सनातन सभ्यता एक ऐसी है जिसके मंदिर आज भी मौजूद हैं। भले ही कर्मकांड के नाम पर उनका महत्व घटाया गया, पर इसी बहाने उन्हें जीवित रखा गया। यही वजह है कि सबसे ज्यादा आक्रमण इसी संस्कृति पर हुए। सनातन समाज ने कभी भारत छोड़कर बिखराव नहीं किया, वरना आबादी घटने पर यहाँ भी कोई सैलाब आता और मंदिर दफन हो जाते।

रावण के महल वाले स्थान पर आज भी सैटेलाइट सिग्नल नहीं मिलते — अयोध्या में भी कई जगह ऐसा है। शायद वहाँ कभी टार्टेरियन जैसी ही वास्तुकला रही हो, जो धंस गई हो, लेकिन विद्युत तरंगें अब भी मौजूद हैं।

रामायण और महाभारत असल में उसी अति आधुनिक युग के इतिहास हैं। लेकिन चालाकी से रामचरितमानस को 600 साल पुराना बताकर असली रामायण की जगह दी गई और महाभारत को भागवत कथा से रिप्लेस किया गया।

कृष्ण ने स्पष्ट कहा था — "यदि युद्ध हुआ तो नगर पृथ्वी में समा जाएंगे और ज्ञान का क्षरण होगा" — यही हुआ, और उस युग का ज्ञान हमेशा के लिए खत्म हो गया।

जब पुराना किला, दिल्ली में प्राचीन इंद्रप्रस्थ के प्रमाण मिलते हैं तो खुदाई धीमी कर दी जाती है। जो बोलता है उसे चुप करा दिया जाता है। द्वारका के डूबने की कहानी भी टार्टेरियन के पतन जैसी ही है — हर सभ्यता का अंत एक जैसे पैटर्न पर हुआ।

ये सब केवल संयोग नहीं हो सकता।

एक समाचार, कई शीर्षक

विजय गर्ग

एक समाचार, कई शीर्षक₹ पर प्रकाश डाला गया है कि कैसे एक भी घटना को कई तरीकों से तैयार किया जा सकता है, जिससे विभिन्न सुर्खियों में आता है। यह मीडिया परिदृश्य में एक आम घटना है और कई कारकों से प्रभावित है, जिनमें शामिल हैं: 1.। पूर्वाग्रह और परिप्रेक्ष्य:

राजनीतिक पूर्वाग्रह: एक नई सरकारी नीति के बारे में एक कहानी एक सरकार समर्थक आउटलेट द्वारा शीर्षक हो सकता है के रूप में ₹[देश] अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए साहसिक कदम लेता है₹ जबकि एक विपक्षी झुकाव आउटलेट लिख सकता है, ₹नई नीति छोटे व्यवसायों धमकी, आलोचकों चेतावनी.₹ नीति के तथ्य समान हैं, लेकिन फ्रेमिंग और फोकस पूरी तरह से अलग हैं।

वैचारिक या सामाजिक पूर्वाग्रह: एक विरोध के बारे में एक कहानी को बाएं झुकाव वाले प्रकाशन द्वारा ₹प्रदर्शनकारियों की मांग में बदलाव, सामाजिक अन्याय का हवाला देते हुए₹ शीर्षक दिया जा सकता है, जबकि एक सही झुकाव वाला प्रकाशन इसे शीर्षक दे सकता है, ₹ट्रैफिक को अनियंत्रित क्राउड

ब्लॉक सिटी सड़कों के रूप में बाधित किया गया।₹ प्रदर्शन के कारण से जनता पर इसके प्रभाव पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 2.। जोर और कोण:

मानव तत्व पर ध्यान दें: एक प्राकृतिक आपदा कहानी में एक शीर्षक हो सकता है जो दुख और वीरता पर जोर देता है: ₹बाढ़ विनाशकारी बाढ़ के बाद पड़ोसियों को बचाने के लिए सामुदायिक रैलियां।₹

आर्थिक प्रभाव पर ध्यान दें: एक ही घटना को एक शीर्षक के साथ कवर किया जा सकता है जैसे: ₹बाढ़ का नुकसान लागत अरबों के लिए अपेक्षित, आर्थिक सुधार अनिश्चित।₹

राजनीतिक पतन पर ध्यान दें: एक और शीर्षक सरकार की प्रतिक्रिया को उजागर कर सकता है: ₹बाढ़ संकट के लिए धीमी प्रतिक्रिया के लिए आग के तहत नेता।₹ 3.। प्रारूप और संदर्भ:

खोज इंजन अनुकूलन (एसईओ): ऑनलाइन प्रकाशन अक्सर उन सुर्खियों का उपयोग करते हैं जो खोज इंजन के लिए अनुकूलित होते हैं, जिनमें ऐसे कीवर्ड शामिल होते हैं जिन्हें लोगों को खोजने की संभावना होती है। उदाहरण के लिए, एक शीर्षक एक प्रत्यक्ष प्रश्न का उत्तर देने के लिए ₹यहां आपको नए कर कानून के बारे में जानने की आवश्यकता हैर हो सकता है।

कुछ सुर्खियों में सनसनीखेज होने और क्लिक प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा भड़काने के लिए डिज़ाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, एक शीर्षक हो सकता है ₹आप विश्वास नहीं करेंगे कि राष्ट्रपति ने अपने भाषण में क्या कहा₹ बजाय एक अधिक सीधा सारांश।

सोशल मीडिया: ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर, तेज गति से चलने वाले फीड में बाहर खड़े होने के लिए सुर्खियों को छोटा, छिद्रपूर्ण और ध्यान खींचने की आवश्यकता होती है। संक्षेप में, एक शीर्षक का विकल्प एक शक्तिशाली उपकरण है। यह पूरे लेख के लिए टोन सेट कर सकता है, जनमत को आकार दे सकता है, और यहां तक कि एक समाचार कहानी के बारे में लोगों को जो याद है उसे प्रभावित कर सकता है। एक ही घटना के लिए विभिन्न सुर्खियों का विश्लेषण मीडिया पूर्वाग्रह और विभिन्न कोणों को समझने का एक शानदार तरीका है जिनसे एक कहानी बताई जा सकती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्

भारत, सैकड़ों बोली जाने वाली भाषाओं का घर, पर सभी देशवासियों एक दिल के साथ मार्च करते है

विजय गर्ग

भारत की भाषाई विविधता का जश्न मनाते हुए, सरकार समावेशी और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है - विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार करती है और क्षेत्रीय भाषाओं को राष्ट्रीय एकता और गौरव के स्तंभ के रूप में बढ़ाती है

भारत के रूप में समृद्ध रूप से विविध देश में, सैकड़ों बोली जाने वाली भाषाओं और अनगिनत बोलियों का घर, भाषा हमेशा संचार के साधन से अधिक रही है। यह पहचान, विरासत और संस्कृति है। लेकिन गलत हाथों में, यह विभाजन के लिए एक उपकरण भी बन सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने भाषाई भेदभाव की राजनीति को दृढ़ता से खारिज कर दिया है और इसके बजाय एक एकीकृत, समावेशी दृष्टिकोण अपनाया है जो हर क्षेत्रीय जीभ को एक राष्ट्रीय खजाने के रूप में मनाता है।

बार-बार, पीएम मोदी ने प्रदर्शित किया है कि भारत की भाषाई बहुलता प्रबंधन करने के लिए एक चुनौती नहीं है, बल्कि एक ताकत है। राज्य की स्थानीय भाषा में अपने भाषणों की शुरुआत से ही वह संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक प्लेटफार्मों पर तमिल जैसी शास्त्रीय भाषाओं का सम्मान करने के लिए जाते हैं, उनकी सरकार ने भाषा को राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बना दिया है। यह आकस्मिक नहीं है। यह 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास' में विश्वास रखने वाली सरकार के लोकाचार का केंद्र है

भाषाई विरासत

मोदी सरकार ने भारत की भाषाई और सांस्कृतिक समृद्धि को पहचानने और संरक्षित करने में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और संस्कृत की मौजूदा सूची को जोड़ते हुए 2024 में मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। ग्यारह भारतीय भाषाएं अब इस स्थिति का आनंद लेती हैं, भाषाई विरासत को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का एक वसीयतनामा।

'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' जैसी पहल ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया है। काशी-तमिल संगम, काशी-तेलुगु संगम, और काशी-सौराष्ट्र संगम भाषा के प्रमुख उदाहरण हैं जिनका उपयोग क्षेत्रों को जोड़ने के लिए किया जाता है, उन्हें विभाजित नहीं किया जाता है। वन क्लास के तहत 200 बजे से अधिक ई-विद्या चैनल, क्षेत्रीय भाषाओं में स्कूली शिक्षा प्रसारित करने के लिए एक चैनल योजना भी शुरू की गई है, जो कम उम्र से भाषाई समावेश सुनिश्चित करती है।

अपनी भाषा में भारतीयों को सशक्त बनाना

मोदी सरकार की ऐतिहासिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020) एक परिवर्तनकारी पहल है जो इस भाषाई प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, छात्रों को अब अपनी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में, विशेष रूप से प्राथमिक और तकनीकी शिक्षा में सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इंजीनियरिंग और चिकित्सा पाठ्यक्रमों का हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती और बंगाली सहित कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जा रहा है, यह सुनिश्चित करते हुए कि भाषा के कारण किसी भी छात्र को अवसर से बाहर नहीं रखा गया है।

नीति एक भाषा को दूसरे पर थोपने के बारे में नहीं है, बल्कि पहुंच बनाने के बारे में है ताकि शिक्षा के माध्यम से सीखने में बाधा न आए। यह औपनिवेशिक युग के शिक्षा मॉडल के विपरीत है, जिसने अंग्रेजी और अपने मूल सांस्कृतिक संदर्भ से पीढ़ियों को अलग कर दिया। मोदी सरकार की दृष्टि कक्षा में नहीं रुकती। एसएससी, जेईई, नीट युजी और युजीसी-एनईटी, जैसी प्रतियोगी परीक्षाएं अब सभी 22 अनुसूचित भाषाओं में इसका विस्तार करने के लिए रोडमैप के साथ 13 से 15 भारतीय भाषाओं में आयोजित की जा रही हैं। कर्मचारी चयन आयोग ने विभिन्न राज्यों से लंबे समय से चली आ रही मांगों को संबोधित करते हुए और लाखों युवाओं की संभावनाओं में सुधार करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी मातृभाषा में परीक्षा देने की अनुमति देने के लिए अपने प्रारूप का अनावरण किया है।

तीन-भाषा नीति

एनईपी के तहत प्रस्तावित तीन-भाषा नीति के आसपास विपक्ष द्वारा काफी हद तक बहुत विवाद उत्पन्न किया गया है। हमें स्पष्ट होना चाहिए। यह नीति हिंदी या किसी अन्य भाषा को लागू करने के बारे में नहीं है। यह भारतीयों को अधिक भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए प्रोत्साहित करने के बारे में है, ठीक उसी तरह जैसे अंग्रेजी लोकप्रिय हुई क्योंकि यह व्यापक रूप से सिखाया और उपलब्ध था।

भाषाई तर्ज पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद 1956 के बाद के युग में पहली बार पेश किया गया तीन भाषा का सूत्र प्रशासनिक सुविधा और राष्ट्रीय सामंजस्य के लिए था, जबरदस्ती नहीं। मोदी सरकार बस इसे एक आधुनिक, समावेशी व्याख्या दे रही है। भाषाई विविधता को प्रोत्साहित करना एकरूपता को लागू करने के समान नहीं है। वास्तव में, नीति क्षेत्रीय वरीयता और व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर भाषाओं को चुनने की लचीलापन प्रदान करती है।

यह औपनिवेशिक और औपनिवेशिक नीतियों द्वारा दिए गए नुकसान को ठीक करने की दिशा में एक कदम है जो देशी भाषाओं पर अंग्रेजी को प्राथमिकता देता है। भारत अब एक डिजिटल, शैक्षिक और प्रशासनिक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर रहा है जहां कोई भी नागरिक भाषा के कारण पीछे नहीं रहता है।

डिवीजन का खतरनाक खेल

मोदी सरकार के समावेशी दृष्टिकोण के विपरीत, विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, ने लगातार विभाजनकारी बयानबाजी की है। चाहे वह हिंदी थोपने का भय पैदा कर रहा हो या उत्तर-दक्षिण के द्विग्रहों को बढ़ावा दे रहा हो, उनकी रणनीति पहचान की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए भाषा को हथियार बनाने पर टिका है। उदाहरण के लिए, कांग्रेस के एक सांसद ने हाल ही में सुझाव दिया कि दक्षिण भारत को आर्थिक असंतुलन के लिए तथाकथित ₹हिंदी क्षेत्र₹ को दोष देते हुए एक अलग देश की मांग करनी चाहिए। इस तरह के बयान सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं हैं। वे खतरनाक रूप से देशद्रोही हैं।

यह राहुल गांधी के राजनीतिक आउटरीच के खिलाफ है जिसका शीर्षक है ₹भारत जोडो₹। ऐतिहासिक रूप से, कांग्रेस ने भाषाई आंदोलनों की अध्यक्षता की है, कुछ क्षेत्रों का पक्ष लिया है, और भारतीय भाषाओं के संरक्षण की उपेक्षा की है। अब भी, जब मोदी सरकार क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां शुरू करती है, तो विपक्ष कथा को विकृत करता है, इसे प्रमुख या ₹प्रतिगामी₹ कहता है सच्चाई से आगे कुछ नहीं हो सकता।

एकता के लिए एक कॉल, एकरूपता नहीं

मोदी सरकार की भाषा नीति भारत की सांस्कृतिक विविधता और समावेश के माध्यम से सशक्तिकरण में दृढ़ विश्वास के लिए गहरे सम्मान में निहित है। यह टॉप-डाउन थोपने के पुराने मॉडल को खारिज करता है और एक बॉटम-अप दृष्टिकोण को गले लगाता है, एक जो राष्ट्रीय कपड़े में बुनाई करते समय क्षेत्रीय पहचान को मजबूत करता है।

संसद में संविधान की 75 वीं वर्षगांठ के दौरान, प्रधान मंत्री ने टिप्पणी की कि भारत की विविधता का जश्न बाबासाहेब अम्बेडकर के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने रेखांकित किया कि सरकार की नीतियों का उद्देश्य राष्ट्र को एकजुट करना है - इसे विभाजित नहीं करना है - और भाषाई गर्व की लंबे समय से चली आ रही उपेक्षा को उलटना है जो पिछले दशकों से हुई है।

भारत का भविष्य समरूपता में नहीं बल्कि सामंजस्य में है। एक 'विक्सित भारत' केवल तभी बनाया जा सकता है जब प्रत्येक भारतीय, अपनी भाषा की परवाह किए बिना, सुना, सम्मानित और शामिल महसूस करता है।

पीएम मोदी की दृष्टि एक भाषा को दूसरी भाषा से बदलने के लिए नहीं बल्कि एक ऐसा समाज बनाने के लिए है जहां हर भाषा प्रगति का वाहन है। आइए हम विभाजनकारी राजनीति को अस्वीकार करें जो एक क्षेत्र को दूसरे के खिलाफ और एक भाषा को दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। आइए हम विविधता में एकता के विचार को गले लगाएं

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट

भारतीय महिलाएं देर से शादी कर रही हैं और सिंगल रह रही हैं: क्यों?

विजय गर्ग

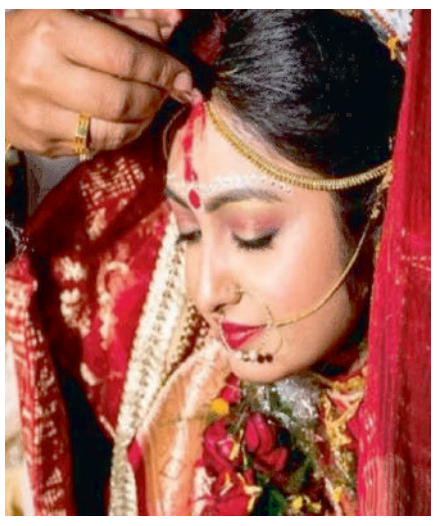

भारतीय महिलाओं के जीवन में बाद में शादी करने या एकल रहने का चयन करने की बढ़ती प्रवृत्ति सामाजिक और आर्थिक कारकों के संगम से प्रेरित एक जटिल घटना है। यह बदलाव पारंपरिक मानदंडों से प्रस्थान का प्रतिनिधित्व करता है, जहां विवाह को अक्सर एक महिला का प्राथमिक उद्देश्य और सुरक्षा का स्रोत माना जाता था। इस प्रवृत्ति के पीछे कुछ प्रमुख कारण यहां दिए गए हैं: 1.। शिक्षा और कैरियर आकांक्षाएं

व्यक्तिगत और व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राथमिकता देना: एक महत्वपूर्ण कारक महिलाओं के लिए शैक्षिक प्राप्ति और कैरियर के अवसरों में वृद्धि है। कई अब शादी को लेकर अपनी पढ़ाई, पेशेवर विकास और वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके लिए, एक कैरियर अब शादी से पहले एक अस्थायी चरण नहीं है, बल्कि सुरक्षा का एक स्रोत और उनकी पहचान का एक परिभाषित हिस्सा है।

₹सुरक्षा₹ कथा को चुनौती देते हुए: ऐतिहासिक रूप से, शादी को एक महिला के ₹सुरक्षा जाल₹ के रूप में देखा गया था। हालांकि, बढ़ती वित्तीय स्वतंत्रता के साथ, कई महिलाएं खुद का समर्थन करने में सक्षम महसूस करती हैं और अब शादी को अस्तित्व की आवश्यकता के रूप में नहीं देखती हैं।

रिश्तों में समानता की मांग: उच्च शिक्षित और पेशेवर रूप से सफल महिलाओं को असमान साझेदारी के लिए बसने की संभावना कम है। वे एक ऐसे साथी की तलाश करते हैं जो अपनी महत्वाकांक्षाओं का सम्मान करता है, जिम्मेदारियों को साझा करता है, और रिश्ते को एक पदानुक्रमित के बजाय ₹साझा यात्रा₹ के रूप में देखता है। जब उन्हें यह नहीं मिलता है, तो वे अधिक आरामदायक शेष एकल होते हैं। 2.। बदलते सामाजिक मानदंड और उम्मीदें

एक महिला के मूल्य को फिर से परिभाषित करना: पारंपरिक विश्वास जो एक महिला के मूल्य को उसकी वैवाहिक स्थिति से बंधा हुआ है, उसे चुनौती दी जा रही है। आधुनिक भारतीय महिलाएं अपनी शर्तों पर सफलता और पूर्ति को फिर से परिभाषित कर रही हैं, इस विचार को गले लगाते हुए कि विवाह एक विकल्प है, दायित्व नहीं।

दुखी विवाह का अवलोकन करना: कई महिलाएं बड़ी हो गई हैं, जो पिछली पीढ़ियों के विवाह के समझौते और नाखुशी को देख रही हैं, जो अक्सर वास्तविक अनुकूलता के बजाय सामाजिक दबाव पर आधारित थीं। इसने उन्हें ऐसी ही स्थिति में आने के लिए सतर्क और अनिच्छुक बना दिया है।

सशक्तिकरण और स्वायत्तता: शिक्षा और रोजगार की बढ़ती पहुंच ने महिलाओं को उनके जीवन विकल्पों पर अधिक नियंत्रण दिया है। उन्हें इस बारे में अपने निर्णय लेने का अधिकार है कि वे कब और किससे शादी करें, या यदि वे शादी करना चाहते हैं। यह स्वायत्तता उन्हें व्यक्तिगत विकास और आत्म-खोज को प्राथमिकता देने की अनुमति देती है। 3.। विवाह बाजार और संगतता मुद्दे

₹विवाह प्रतियोगिता₹: जैसा कि महिलाएं अधिक शिक्षित और सफल होती हैं, वे अक्सर पाते हैं कि पात्र पुरुष भागीदारों का पूल जो अपने मानदंडों को पूरा करता है - जैसे कि समान रूप से शिक्षित, आर्थिक रूप से स्थिर और अपने कैरियर का समर्थन करना - सिकुड़ सकता है।

सेटल से इनकार: आधुनिक महिलाएं एक साथी में जो चाहती हैं और उसकी जरूरत के बारे में अधिक निश्चित होती जा रही हैं। वे एक औसत दर्जे का या बेमेल रिश्ते के लिए ₹बसने₹ के लिए कम तैयार हैं, एक दुखी शादी में होने की तुलना में एकल होना पसंद करते हैं। अनुकूलता और आपसी सम्मान की यह इच्छा शादी में देरी का एक महत्वपूर्ण कारण है।

सोशल स्टिग्मा, लेकिन एक बैरियर के कम: जबकि अभी भी एकल महिलाओं के आसपास कुछ सामाजिक निर्णय है, विशेष रूप से एक सामूहिक संस्कृति में जो परिवार पर जोर देती है, एकल महिलाओं की बढ़ती संख्या एक नया और अधिक दृश्यमान जनसांख्यिकीय पैदा कर रही है। यह, वित्तीय स्वतंत्रता के साथ संयुक्त, कलंक को एक बार की तुलना में एक बाधा से कम बनाता है। सारांश में, बाद में शादी करने या एकल रहने वाली भारतीय महिलाओं की प्रवृत्ति विद्रोह का संकेत नहीं है, बल्कि उनकी बढ़ती स्वतंत्रता, बदलते मूल्यों और रिश्तों में व्यक्तिगत पूर्ति, कैरियर और समानता को प्राथमिकता देने के लिए एक सचेत निर्णय का एक शक्तिशाली प्रतिबिंब है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल, शैक्षिक स्तंभकार, प्रख्यात शिक्षाविद्, गली कौर चंद एमएचआर मलोट पंजाब

धरती की साँसों को राहत देता विकल्प: जैव ईंधन

हर सांस जो हम भरते हैं, हर किरण जो सूरज से झरती है, और हर बूंद जो पृथ्वी को सींचती है — प्रकृति की ये सभी सौगातें हमें अनमोल जीवन देती हैं। लेकिन क्या हम वास्तव में इस जीवनदायिनी प्रकृति के ऋण को समझ पा रहे हैं? आधुनिकता की अंधी दौड़ में हमने जीवाश्म ईंधनों की लत में धरती को इतना प्रदूषित कर दिया है कि अब वह खुद कराहने लगी है। इन्हीं कराहों को सुनकर, हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है — एक ऐसा दिन जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम ऊर्जा के स्रोतों को लेकर किस दिशा में जा रहे हैं, और क्या कोई हरित विकल्प हमारे हाथ में है। यह दिन केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक आह्वान है — एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ने का, जहां ऊर्जा का स्रोत न केवल टिकाऊ हो, बल्कि धरती के प्रति हमारी जिम्मेदारी को भी दर्शाए।

जैव ईंधन की शुरुआत 1893 में सर रूडॉल्फ डीज़ल ने मूंगफली के तेल से इंजन चलाकर की, जो आज पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने वाली क्रांति बन चुका है। बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल जैसे जैव ईंधन गन्ना, मक्का, शैवाल और कृषि अपशिष्ट से बनते हैं, जो जीवाश्म ईंधनों की तुलना में कम कार्बन उत्सर्जन करते हैं और कार्बन चक्र को संतुलित रखते हैं। विश्व बैंक (2022) के अनुसार, जैव ईंधन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 20-60% तक कम हो सकता है, जो जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रभावी कदम है।

भारत, जहां 70% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, में जैव ईंधन का महत्व अत्यधिक है। संशोधित राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2022 के तहत, सरकार ने 2025-26 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे भारत की 80% कच्चे तेल आयात पर निर्भरता कम होगी और किसानों को फसलों व अपशिष्टों से अतिरिक्त आय मिलेगी। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में गन्ने से बायोएथेनॉल उत्पादन ने लाखों किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त किया। 2023 में 4.3 बिलियन लीटर बायोएथेनॉल उत्पादन से 50,000 करोड़ रुपये की तेल आयात बचत हुई, जो ऊर्जा आत्मनिर्भरता और ग्रामीण आर्थिक क्रांति का प्रतीक है।

जैव ईंधन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है इसका पर्यावरणीय प्रभाव। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, वायु प्रदूषण हर साल वैश्विक स्तर पर 70 लाख से अधिक असमय मृत्यु का कारण बनता है। जीवाश्म ईंधनों से चलने

वाले वाहनों का धुआं सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों को वायुमंडल में छोड़ता है। इसके विपरीत, बायोडीज़ल और बायोएथेनॉल से चलने वाले वाहन 30-50% कम प्रदूषक उत्सर्जन करते हैं, जिससे शहरी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार होता है। दिल्ली जैसे शहर, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) अक्सर खतरनाक स्तर को छूता है, जैव ईंधन का उपयोग एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है।

हालांकि, जैव ईंधन की राह में कई चुनौतियां भी हैं। पहली पीढ़ी के जैव ईंधन, जो खाद्य फसलों जैसे मक्का और गन्ने से बनते हैं, खाद्य सुरक्षा पर दबाव डाल सकते हैं। विश्व खाद्य संगठन (एफएओ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 10% जैव ईंधन उत्पादन खाद्य फसलों पर निर्भर है, जिससे खाद्य कीमतों में 5-10% की वृद्धि हो सकती है। इस समस्या से निपटने के लिए दूसरी पीढ़ी (2जी) और तीसरी पीढ़ी (3जी) के जैव ईंधन पर ध्यान देना जरूरी है। 2जी जैव ईंधन कृषि अपशिष्ट, जैसे भूसा और गन्ने की खोई, से बनते हैं, जबकि 3जी जैव ईंधन शैवाल और सूक्ष्मजीवों जैसे गैर-खाद्य स्रोतों से। भारत में, पुणे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की 2जी बायोएथेनॉल रिफाइनरी एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो प्रतिदिन 100 किलोलीटर बायोएथेनॉल का उत्पादन कर रही है।

जैव ईंधन के क्षेत्र में तकनीकी नवाचार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। शैवाल-आधारित जैव ईंधन, जो तीसरी पीढ़ी का हिस्सा हैं, एक एकड़ में पारंपरिक फसलों की तुलना में 10 गुना अधिक ईंधन उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा, शैवाल कार्बन डाई-आक्साइड को अवशोषित करते हैं, जिससे वे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दोहरी भूमिका निभाते हैं। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) के अनुसार, 2050 तक वैश्विक ऊर्जा मिश्रण में जैव ईंधन की हिस्सेदारी 27% तक बढ़ सकती है, बशर्ते तकनीकी और नीतिगत समर्थन मिले।

जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक और शैक्षिक जागरूकता को और प्रभावी ढंग से बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत में ग्रामीण समुदायों को जट्रोफा की खेती या बायोगैस संयंत्रों की स्थापना जैसे जैव ईंधन उत्पादन से जोड़ना न केवल उनकी आय को बढ़ाएगा, बल्कि ऊर्जा साक्षरता को भी गति देगा। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में जैव ऊर्जा पर केंद्रित पाठ्यक्रम शुरू करने से युवा वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में अनुसंधान के लिए प्रेरित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली और खड़गपुर में स्थापित जैव ऊर्जा शोध केंद्र नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस दिशा में एक मज़बूत कदम है।

वैश्विक स्तर पर भी जैव ईंधन का महत्व बढ़ रहा है। ब्राजील, जो बायोएथेनॉल उत्पादन में विश्व नेता है, ने 2023 में 35 बिलियन लीटर बायोएथेनॉल का उत्पादन किया, जो इसके कुल ईंधन खपत का 30% है। अमेरिका और यूरोपीय संघ भी बायोडीज़ल और बायोएथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा दे रहे हैं। भारत इन देशों से प्रेरणा ले सकता है, लेकिन इसके लिए नीतिगत स्थिरता, निवेश, और बुनियादी ढांचे के विकास की जरूरत है।

विश्व जैव ईंधन दिवस हमें यह याद दिलाता है कि ऊर्जा का भविष्य केवल तकनीक में नहीं, बल्कि हमारी सोच और व्यवहार में बदलाव में निहित है। यह एक अवसर है कि हम अपने दैनिक जीवन में छोटे-छोटे कदम उठाएं — जैसे बायोडीज़ल से चलने वाली गाड़ियों को प्राथमिकता देना, बायोगैस संयंत्रों को अपनाना, या अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान देना। यह दिन हमें यह भी सिखाता है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हो सकते हैं।

जैव ईंधन केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि एक दर्शन है — एक ऐसी दुनिया का दर्शन, जहां मानव और प्रकृति एक-दूसरे के साथ सामंजस्य में रहें। यह हमें उस जिम्मेदारी की याद दिलाता है कि हमारी हर पसंद, चाहे वह ऊर्जा का चयन हो या जीवनशैली, धरती के भविष्य को प्रभावित करती है। 10 अगस्त का यह दिन हमें प्रेरित करता है कि हम न केवल उपभोक्ता बनें, बल्कि प्रकृति के संरक्षक भी बनें। यह एक नई शुरुआत का आह्वान है — एक ऐसी शुरुआत, जो हरित, स्वच्छ, और टिकाऊ भविष्य की नींव रखे।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत",
बड़वानी (मप्र)

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बढ़ता अमेरिकी आतंक और भारत

प्रो. महेश चंद गुप्ता

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण अमेरिका लंबे समय से वैश्विक आर्थिक नीतियों पर दबदबा बनाए हुए है। यह दबदबा अब खुलेआम दादागिरी का रूप ले चुका है, खासकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मनमाने टैरिफ लगाकर देशों को आर्थिक रूप से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा ने इस दादागिरी को और स्पष्ट कर दिया है, यानी कुल मिलाकर 50 फीसदी का टैरिफ — यह न सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन पर भी असर डालेगा।

ट्रंप को भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति है जबकि विडंबनायह है कि चीन भी यही कर रहा है और अमेरिका स्वयं रूस से यूरेनियम और खाद खरीद रहा है, यानी सिद्धांत और व्यवहार में अमेरिकी नीति दोहरे मानदंडों से भरी है। सवाल यह है कि भारत क्यों अपने हितों को ताक पर रखकर अमेरिकी दबाव में काम करे?

कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत पर टैरिफ बढ़ोतरी के एलान के बाद पहली बार एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिक्रिया ने भारत के अडिग रुख को और मजबूती से सामने रखा है। उससे भारत का अडिग रवैया परिलक्षित हो रहा है। मोदी ने साफ कह दिया है कि हमारे लिए, हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह वक्तव्य बताता है कि भारत अब वैश्विक दबावों के आगे नतमस्तक नहीं होगा।

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) के आंकड़ों के अनुसार भारत-अमेरिका के बीच वार्षिक व्यापार 11 लाख करोड़ रुपये का है। भारत अमेरिका को 7.35 लाख करोड़ रुपये का निर्यात करता है जिसमें दवाइयाँ, दूरसंचार उपकरण, जेम्स-एंड-ज्वेलरी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं। वहीं, अमेरिका से भारत 3.46 लाख करोड़ रुपये का आयात करता है जिसमें कच्चा तेल, कोयला, हीरे, विमान व अंतरिक्ष यानों के पुर्जे शामिल हैं।

लेकिन यहां चिंता की बात यह है कि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर अमेरिका ने इतना भारी शुल्क नहीं लगाया है, जिससे उनके उत्पाद भारतीय उत्पादों की तुलना में अमेरिकी बाजार में सस्ते पड़ेंगे। फिर भी, मोदी सरकार का रवैया दृढ़ है। साठ के दशक में हम गेहूं, दूध के लिए भी अमरीका पर निर्भर थे लेकिन लगता है ट्रंप ने उन दिनों लिखी गई कोई किताब ताजा मानकर पढ़ ली है। उन्हें आज भी पुराना भारत दिख रहा है जिसे वह झुकाने की सोच रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। वह आत्मनिर्भर एवं विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था है। भारत का पूरे विश्व में दबदबा बढ़ रहा है।

उद्योग जगत भी इस दबाव को एक अवसर के रूप में देख रहा है। उद्योगपति हर्ष गोयनका का कहना है कि अमेरिका निर्यात पर टैरिफ लगा सकता है लेकिन हमारी संप्रभुता पर नहीं। आनंद महिंद्रा ने तो यह भी कहा कि जैसे 1991 के विदेशी मुद्रा संकट ने उदारीकरण की राह खोली थी, वैसे ही यह टैरिफ संकट भी हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में गति दे सकता है। ललित मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप को 2023 की उस रिपोर्ट की याद दिलाई है जो अमेरिका की कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने ही जारी की थी। गौरतलब है कि गोल्डमैन सैक्स ने इस रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है जो न केवल जापान और जर्मनी, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में अनुमान है कि 2075 तक भारत की जीडीपी 52.5 ट्रिलियन डॉलर होगी जो चीन के 57 ट्रिलियन डॉलर से कम लेकिन अमेरिका के 51.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगी। वर्तमान में, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ रही है।

अमेरिका की आर्थिक दादागिरी कोई नई बात नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही वह वैश्विक आर्थिक नीतियों में अपनी शर्तें थोपता आया है लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन पहले ही उसके दबाव में नहीं आ रहा और अब भारत भी साफ संकेत दे रहा है कि उसकी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हित हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाक युद्ध रोकने का श्रेय लेने की अमेरिकी कोशिश को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। यही रुख अब टैरिफ विवाद में भी नजर आ रहा है।

मोदी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और इंडिया फर्स्ट जैसी नीतियों के जरिये 2047 तक भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ राजनीति भारत के आत्मनिर्भरता अभियान को और तेज कर सकती है।

धैर्य और संयम के साथ नेतृत्व करना भारत की ताकत है। रामचरितमानस का वह प्रसंग याद आता है जब विभीषण ने युद्ध के समय श्रीराम से कहा कि रावण के पास सब कुछ है, पर आपके पास कुछ नहीं। तब श्रीराम ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति धैर्य, शांति और सहनशीलता है। यही नीति आज भारत के नेतृत्व में झलक रही है. जहां ट्रंप अभिमान में हैं, वहीं भारत दृढ़ता और शांति के साथ आगे बढ़ रहा है।

इतिहास ने साबित किया है कि अमेरिका कभी भी भारत का स्थायी मित्र नहीं रहा। ट्रंप की नीतियों का विरोध अमेरिका के भीतर भी हो रहा है। ऐसे में बदलते समीकरण भारत के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। ट्रंप भले ही मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं पर वह भी फंस रहे हैं।

टैरिफ के मुद्दे पर उनका अमरीका में भी विरोध हो रहा है। बदले परिदृश्य मे नए वैश्विक समीकरण बनने की संभावनाएं हैं। ट्रंप का रुख चीन के साथ भारत के संबंधों को बदल सकता है।

पीएम मोदी इस महीने के आखिर में सात सालों के बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वह वहां तिआनजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन (एसीओ) समिट में शामिल होंगे। मोदी का यह चीन दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है, जब दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिशें चल रही हैं। भारत बहुत बड़ा बाजार है जिसकी चीन को सख्त जरूरत है। भारत मे जब भी स्वदेशी का मुद्दा उठता है तो चीन इसे अपने खिलाफ मानता है। स्वदेशी की अवधारणा का चीनी उत्पादों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में चीन क्यों नहीं चाहेगा कि उसके भारत के साथ संबंध मधुर हों, खासकर तब जब अमरीका खुद ही भारत से दूरियां बढ़ा रहा है। चीन को भारत के विशाल बाजार की जरूरत है, और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में दूरी बढ़ने से बीजिंग अपने संबंध सुधारने को उत्सुक होगा।

अमेरिका की आर्थिक दादागिरी भले ही अभी भी जारी हो पर बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत का आत्मविश्वास, अडिग रुख और दूरदर्शी नेतृत्व इसे न सिर्फ झेलने में सक्षम है बल्कि इसे अपने विकास की सीढ़ी भी बना सकता है। आने वाले समय में अपने हितों की रक्षा करते हुए दुनिया में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना ही भारत की असली ताकत होगी । अर्थव्यवस्था के शिखर पर पहुंचकर भी भारत वसुधैव कुटुंबकम के मार्ग पर चलेगा। सबका कल्याण ही भारत की सोच है। हम तो प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः ही सोच रखते हैं। दादागिरी हमारा स्वभाव नहीं है।

(लेखक विख्यात शिक्षा विद्, विचारक, चिंतक और वक्ता हैं।)

व्यंग्य : भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है ?

भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों में क्या अंतर है ? देखिए पत्रकार महोदय आपका सवाल एकदम वाजिब है ? इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों ही हवाओं की तरह होती है जो एक तरफ होती है किसी काम को पुरा करवाने के लिए।

वैसे मैं साहित्यकार होने के नाते आपकी अपेक्षा मेरा ज्ञान कम ही होगा क्योंकि आप बुद्धिजीवियों की श्रेणी में आते हैं । वैसे दिनकर जी से पहले और कुछ समय बाद के समय में मेरे पूर्वज साहित्यकारों को बहुत अधिक से अधिक सम्मान मिलता था । परंतु आज आधुनिकता की अंधी दौड़ में कुछ स्वार्थी किस्म के तथाकथित व्हाट्सएप्प यूनिवर्सिटी से प्राप्त ज्ञान के आधार पर " कहीं ईंट कहीं का रोड़ा भानुमति का कुनबा जोड़ा " को आधार बनाकर साहित्य रचकर अपने आप को इतना बड़ा साहित्यकार मानते हैं उनके आगे बच्चन जी , महादेवी वर्मा जैसे कई महान साहित्यकार से भी बड़ा " महान " साहित्यकार अपने आप को मानते हैं इस विकट परिस्थितियों में मुझ जैसे साहित्यकार की कोई गिनती नहीं है फिर भी आपने मुझे इतनी " इज्जत " दी उसके लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद एवं धन्यवाद देता हूं कि , आपने पत्रकारिता का औपचारिक " धर्म " निभाते हुए आपकी सक्रीयता को धन्यवाद देता हूं कि , आपने इस तरह का सवाल पूछा ।

साहित्यकार होने के नाते साहित्यिक नजरीएं से मुझे ऐसा महसूस होता है कि , भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी व्याकरण की दृष्टि से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है वैसे समय और परिस्थितियों को देखकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी को एक ही लिंग मान सकते हैं । परंतु किसी कार्य को अंज्ञाम देने से कोई अलग लिंग होता है वह उभयलिंगी होता है । भ्रष्टाचार पुल्लिंग में और भ्रष्टाचारी स्त्रीलिंग में आता है । इन दोनों के मिश्रण से बने किसी कार्य की सफलता को उभयलिंगी कहते हैं । (याने कि , दोनों पक्षों की आपसी रूप से हुएं गोपनीय कार्य का परिणाम है) और उभयलिंगी को न कोई पहचानता , न कोई जानता है लेकिन , इसको हर कोई अपने अपने हिसाब किताब से भाव देते रहते है ।

भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के कारण जनता का और जनता का विकास इन्हीं के आशीर्वाद से टिका हुआ है और फाईलों के " चांदी पैर " लग जाते हैं । हमारे सभी कार्यों की पुर्ण आहुति किसी " आर्थिक अर्थ " से करके सुकुन पहुंचाती है । जिसकी वजह से हमारे अटके हुए कार्य पुरा होने से हमें अपार " शांति " मिलती है । भ्रष्टाचारी एवं भ्रष्टाचार की अपार महिमा के चलते हर तरफ " विकास ही विकास " होते हुए देख रहे हैं इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है । बस पत्रकार जी बुनियादी सवाल तो यही है कि , क्या भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचार की वजह से ही काम होना जरूरी है ? बिना किसी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के नहीं हो सकता है क्या ?

मैं साहित्यकार होने के नाते जनता की इस " अदालत " में सबसे बड़ा सवाल पूछता हूं कि , माननीय " मौन " धारण मंत्री जी कहते हैं कि " ना खाऊंगा , ना खाने दूंगा " तो फिर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी वर्षों से इस काम पर लगें हुए हैं तों उनका क्या होगा ? अपने अपने पदों पर वर्षों से जमे हुए हैं । ऐसे में आपका " मौनी बाबा " बनना समझ में नहीं आ रहा है ? पुछता है ये भारत " भारतीय " साहित्यकार । आपके मौन धारण करने की " कीमत " कब-तक हमें चुकाना होगी ?

प्रकाश हेमावत
ढाटा नगर रतलाम

रक्षाबंधन: क्या वास्तव में निभा रहे हैं भाई-बहन प्रेम और रक्षा का वादा?

रक्षाबंधन केवल राखी बांधने और गिफ्ट देने का त्योहार नहीं, बल्कि भाई-बहन के स्नेह, विश्वास और परस्पर सहयोग का प्रतीक है। आज यह पर्व सोशल मीडिया दिखावे और औपचारिकताओं में सिमटता जा रहा है। भाई-बहन सालभर दूर रहते हैं, पर एक दिन फोटो खिंचाकर 'रिश्ता निभाने' का प्रमाण दे देते हैं। असली रक्षा तब है जब मुश्किल वक्त में दोनों एक-दूसरे का सहारा बनें, चाहे वह भावनात्मक हो या आर्थिक। त्योहार का अर्थ लाइक्स नहीं, बल्कि लाइफ में प्रेज़ेंस है। राखी का धागा केवल कलाई पर नहीं, दिल में भी बांधना जरूरी है।

-डॉ. सत्यवान सौरभ

त्योहार भारत की सांस्कृतिक आत्मा का आईना हैं। वे केवल कैलेंडर में दर्ज तारीखें नहीं होते, बल्कि पीढ़ियों से जुड़ी भावनाओं, रिश्तों और सामाजिक बंधनों का जीवंत प्रतीक होते हैं। रक्षाबंधन भी ऐसा ही एक पर्व है, जो भाई-बहन के रिश्ते को स्नेह, सुरक्षा और विश्वास की डोर में बांधने का प्रतीक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम आज वास्तव में इस पर्व के मूल भाव को निभा रहे हैं, या यह भी अन्य त्योहारों की तरह दिखावे और औपचारिकता के चकाचौंध में खो गया है?

परंपरा से वर्तमान तक की यात्रा

कभी रक्षाबंधन एक ऐसा अवसर था जब बहनें भाई के माथे पर तिलक लगाकर, राखी बांधकर उनसे जीवनभर सुरक्षा और सहयोग का वादा लेती थीं। यह सुरक्षा केवल शारीरिक खतरों से बचाने की नहीं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई में साथ खड़े होने का आश्वासन था। भाई भी पूरे गर्व के साथ इस वादे को निभाते थे। यह रिश्ता घर के आंगन में पनपता, पत्रों में झलकता और जीवनभर निभता था।

मगर आज, राखी बांधना एक 'फोटोजेनिक' इवेंट बन गया है। सोशल मीडिया पर तस्वीरें डालना, महंगे गिफ्ट देना, ऑनलाइन राखी मंगवाना — यह सब असली भावना को छूने के बजाय उसे सतही बना रहा है। भाई-बहन के बीच संवाद घट रहा है, और 'रक्षा' शब्द का दायरा भी सिमटता जा रहा है।

रक्षा का बदलता अर्थ

पुराने समय में बहनें केवल भाई पर निर्भर नहीं रहती थीं, लेकिन उन्हें पता था कि मुसीबत में भाई उनकी ढाल बनेगा। आज के समय में भाई-बहन दोनों ही अपनी-अपनी व्यस्त जिंदगी में इतने उलझ गए हैं कि अक्सर एक-दूसरे की समस्याओं से बेखबर रहते हैं। रक्षा का मतलब अब 'फिजिकल प्रोटेक्शन' से ज्यादा 'फाइनेंशियल हेल्प' या 'इमरजेंसी सपोर्ट' तक सीमित हो गया है।

लेकिन यहां भी एक विडंबना है — जब बहन आर्थिक रूप से सक्षम होती है, तो अक्सर वह भाई की मदद करती है, पर यह भावना रक्षाबंधन के विमर्श में उतनी जगह नहीं पाती। हमारी संस्कृति में अभी भी रक्षा का जिम्मा एकतरफा तरीके से भाई पर डाल दिया जाता है, जबकि आधुनिक रिश्तों में सुरक्षा और सहयोग दोनों तरफ से होना चाहिए।

दिखावे का दौर

सोशल मीडिया के दौर में त्योहार अब निजी अनुभव से ज्यादा सार्वजनिक प्रदर्शन बन गए हैं। राखी की तस्वीर, गिफ्ट का वीडियो, स्टेटस अपडेट — ये सब रिश्ते की असली आत्मा को दबा देते हैं। कई बार भाई-बहन सालभर बात नहीं करते, लेकिन राखी के दिन फोटो खिंचवा कर ऑनलाइन डाल देते हैं ताकि समाज को 'परफेक्ट रिलेशन' का प्रमाण मिल जाए।

यह दिखावा उस सच्चाई को ढक देता है कि कई बहनें घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न या आर्थिक शोषण का शिकार होती हैं और भाई जानते हुए भी चुप रहते हैं। वहीं, कई भाई जीवन की कठिनाइयों में बहनों से भावनात्मक सहयोग चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी केवल 'त्योहार वाले रिश्ते' का जवाब मिलता है।

संवेदनाओं की कमी

रक्षाबंधन का मूल भाव यह था कि भाई-बहन एक-दूसरे की कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बनें। लेकिन आज संवेदनाओं का सूखा पड़ता जा रहा है। रिश्ते भले खून के हों, पर उनमें औपचारिकता और दूरी बढ़ रही है। शहरों में नौकरी, बिज़नेस, और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं के बीच पारिवारिक जुड़ाव कमजोर हो रहा है।

यह स्थिति केवल रक्षाबंधन के लिए नहीं, बल्कि सभी पारिवारिक रिश्तों के लिए चिंता का विषय है। अगर भाई-बहन का रिश्ता भी केवल एक दिन के उत्सव तक सीमित रह गया, तो आने वाले समय में यह त्योहार भी केवल 'फूल, मिठाई और फोटो' का त्योहार बनकर रह जाएगा।

समानता का दृष्टिकोण

आज के समय में रक्षा का अर्थ केवल पुरुष की जिम्मेदारी नहीं हो सकता। बहनों को भी भाइयों के जीवन में समान भूमिका निभानी चाहिए — चाहे वह भावनात्मक समर्थन हो, सलाह हो या मुश्किल समय में कंधा देने की बात। भाई-बहन का रिश्ता तभी सार्थक है जब उसमें बराबरी और परस्पर सहयोग हो।

अगर किसी भाई पर बहन की शादी, पढ़ाई या करियर का बोझ आता है, तो बहन पर भी भाई की जरूरतों को समझने और मदद करने की जिम्मेदारी आती है। यही संतुलन इस रिश्ते को आधुनिक समय में भी प्रासंगिक बनाए रख सकता है।

समाधान की दिशा

हमें यह समझना होगा कि त्योहार का असली मूल्य उसकी रस्मों में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावनाओं में है। भाई-बहन दोनों को अपने रिश्ते की नींव में विश्वास और सहयोग रखना चाहिए, न कि केवल गिफ्ट और फोटो के सहारे इसे निभाना चाहिए। सालभर एक-दूसरे से बात करना, छोटी-छोटी खुशियां और परेशानियां साझा करना ही रिश्ते को जिंदा रखता है। एक फोन कॉल, एक मुलाकात, या मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने का भाव, राखी के धागे से कहीं ज्यादा मजबूत डोर बनाता है। सोशल मीडिया पर दिखाने के बजाय असल में निभाना ज्यादा जरूरी है। राखी का मतलब 'लाइक्स' नहीं, बल्कि लाइफ में प्रेज़ेंस है। भाई-बहन दोनों को एक-दूसरे की सुरक्षा, सम्मान और जरूरत का ख्याल रखना चाहिए। एकतरफा जिम्मेदारी की सोच बदलनी होगी। राखी की रस्म निभाते हुए भी रिश्ते में आधुनिक मूल्यों — जैसे समानता, स्वतंत्रता और व्यक्तिगत सम्मान — को जगह देना जरूरी है।

रक्षाबंधन का असली वादा

रक्षाबंधन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि रिश्तों की असली परीक्षा है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग हैं जिनसे हम बिना किसी स्वार्थ के जुड़े हैं। लेकिन अगर यह जुड़ाव केवल कैलेंडर की तारीख पर ही जीवित होता है, तो इसका असली महत्व खत्म हो जाएगा।

आज जरूरत है कि हम राखी के धागे को केवल कलाई पर नहीं, बल्कि दिल में भी बांधें — ऐसा बंधन, जो साल के 365 दिन स्नेह, सम्मान और सुरक्षा के वादे को निभाए। तभी हम कह पाएंगे कि हम सच में भाई-बहन प्रेम और रक्षा का वादा निभा रहे हैं।

हिमालय में अनियंत्रित विकास नहीं, वैज्ञानिक संतुलन की आवश्यकता

जयसिंह रावत

उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के धराली गांव में अगस्त 2025 में आई भीषण बाढ़ ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में अंधाधुंध और असंवेदनशील विकास किस प्रकार विनाश को आमंत्रित कर रहा है। धराली की यह त्रासदी मात्र एक स्थानीय प्राकृतिक आपदा नहीं थी बल्कि हिमालय क्षेत्र में हो रहे जलवायु परिवर्तन, बेतरतीब निर्माण, वनों की कटाई, नदियों के प्राकृतिक प्रवाह में अवरोध और वैज्ञानिक चेतावनियों की अनदेखी का प्रत्यक्ष परिणाम थी। यह घटना पूरे भारतीय हिमालय की उस त्रासद श्रृंखला की अगली कड़ी है जो केदारनाथ, चमोली, जोशीमठ और सिक्किम जैसी आपदाओं से लगातार बनी हुई है।

धराली में जिस बाढ़ ने दर्जनों भवनों, होमस्टे, दुकानों और होटलों को मलबे में तब्दील कर दिया, वह महज आकस्मिक नहीं थी। स्थानीय भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार, यह क्षेत्र न केवल भूकंपीय दृष्टि से संवेदनशील है बल्कि इस गांव के नीचे से बहने वाली नदी के किनारे बनाए गए अधिकांश निर्माण फ्लड प्लेन यानी बाढ़ क्षेत्र में स्थित थे। परंपरागत पहाड़ी घर सदियों से ढलानों पर बनाए जाते रहे हैं ताकि वे बाढ़ और भूस्खलन से बचे रहें किंतु आधुनिक पर्यटन आधारित अर्थव्यवस्था ने इन नियमों को ताक पर रखकर स्वॉटरफ्रंटस सुविधा के नाम पर घाटी के सबसे निचले हिस्से को व्यवसायिक उपयोग में ला दिया।

धराली की त्रासदी कोई पहली चेतावनी नहीं है। वर्ष 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ क्षेत्र में आई जलप्रलय ने लगभग छह हजार लोगों की जान ली थी। यह आपदा एक जलवायु-संबंधित तीव्र वर्षा, ग्लेशियर झील के विस्फोट और मंदाकिनी नदी के अचानक उफान का घातक संयोग थी। इसके पश्चात 2021 में चमोली जिले के रैणी गांव के पास ऋषिगंगा नदी में एक हिमखंड के गिरने से अचानक बाढ़ आई जिसने निर्माणाधीन पनबिजली परियोजनाओं को तबाह कर दिया और 200 से अधिक लोगों की जान चली गई। इस घटना में स्पष्ट रूप से ग्लेशियर के पिघलने और पर्वतीय पारिस्थितिकी के असंतुलन की भूमिका सामने आई। फिर 2023 में जोशीमठ शहर की भूमि में दरारें और धंसाव की घटनाएं हुईं जिससे हजारों लोग विस्थापित हुए। वहां की वैज्ञानिक रिपोर्टों में बताया गया कि यह संकट भूमिगत जलस्रोतों में बदलाव, अनियोजित निर्माण और पर्वतीय ढालियों के अत्यधिक दोहन का परिणाम था।

केवल उत्तराखंड ही नहीं, सम्पूर्ण हिमालय क्षेत्र ऐसी ही आपदाओं की गिरफ्त में है। वर्ष 2023 में सिक्किम की लोनक झील फटने से अचानक आई बाढ़ ने कई गांवों को तबाह कर दिया। यह झील एक ग्लेशियल लेक थी जो लगातार पिघलते हिमनद के कारण बढ़ती जा रही थी और अंततः अपने ही भार से टूट गई। वैज्ञानिक इसे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF) कहते हैं। 2022 में उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा ग्लेशियर क्षेत्र में हिमस्खलन से 27 पर्वतारोहियों की मौत हुई जो भारत की अब तक की सबसे बड़ी पर्वतारोहण दुर्घटना थी। इससे पहले 1998 में मालपा गांव में हुए

भूस्खलन में 221 लोग मारे गए थे जिनमें कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे तीर्थयात्री भी शामिल थे।

इन आपदाओं की पृष्ठभूमि में सबसे बड़ी भूमिका जलवायु परिवर्तन की है। भारतीय हिमालय में स्थित लगभग 9,575 हिमनदों में से बड़ी संख्या तेजी से पिघल रही है। शोध बताते हैं कि बीसवीं सदी के मुकाबले इक्कीसवीं सदी में हिमालयी ग्लेशियर दोगुनी गति से सिकुड़ रहे हैं। इससे पर्वतीय नदियों में अचानक जलप्रवाह बढ़ जाता है और नई-नई झीलें बन रही हैं जो कभी भी फट सकती हैं। 2020 में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार हिमालय में 3,000 से अधिक ग्लेशियल झीलें जोखिम की श्रेणी में हैं जिनमें से लगभग 200 झीलों से तात्कालिक खतरा है। यदि इनका विस्फोट हुआ तो घाटियों में बसे नगर और गांव जलप्रलय की चपेट में आ सकते हैं।

इसके साथ ही विकास परियोजनाएं भी समस्या को बढ़ा रही हैं। उत्तराखंड में चल रही चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इस परियोजना की समीक्षा में वैज्ञानिकों ने बताया कि पहाड़ों की कटाई अत्यंत खड़ी ढालियों पर की गई है जिससे बड़े पैमाने पर भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी हैं। वर्ष 2023 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस परियोजना के कारण 811 से अधिक भूस्खलन सक्रिय हो चुके हैं। पहाड़ियों को 80 डिग्री तक की ढाल पर काटा गया जो इंजीनियरिंग सिद्धांतों के अनुसार भी अस्वीकार्य है।

साथ ही साथ वनों की कटाई ने भी संकट को और गहराया है। वनों की अनुपस्थिति में वर्षा का जल सीधा ढलानों से बहकर नदी में चला जाता है जिससे तलछट बढ़ती है और जलधाराओं का मार्ग अवरुद्ध होता है। पारंपरिक जलस्रोत जैसे धाराएं और गूलें सूखती जा रही हैं। पर्वतीय जलसंकट भी अब एक नई आपदा बन चुका है जिससे पहाड़ों के समाज को स्थायी रूप से विस्थापन की ओर धकेला जा रहा है।

इन सभी घटनाओं से स्पष्ट है कि हिमालय कोई साधारण पर्वत श्रृंखला नहीं है. यह एक स्जीवित पर्वतस् है जो अभी भी भूगर्भीय दृष्टि से सक्रिय है। भारत और यूरेशिया प्लेटों की टक्कर से उठे इस पर्वत की चट्टानें अभी भी आकार ले रही हैं जिसका परिणाम है कि यह इलाका भूकंपीय दृष्टि से सबसे अधिक संवेदनशील है। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के अधिकांश भाग भूकंपीय क्षेत्र-चार में आते हैं। ऐसे में यहां कोई भी निर्माण कार्य अत्यंत सावधानीपूर्वक और वैज्ञानिक निगरानी में ही किया जाना चाहिए।

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में एक हिमाचल मामले में टिप्पणी की कि केवल राजस्व की प्राप्ति विकास का उद्देश्य नहीं हो सकती। विकास की योजनाएं पर्यावरण और पारिस्थितिकी की कीमत पर नहीं बननी चाहिए। न्यायालय ने यह भी कहा कि पहाड़ी राज्यों में नए निर्माण कार्यों में भूगर्भीय सर्वेक्षण, पारंपरिक ज्ञान और स्थानीय समुदायों की सहमति को महत्व दिया जाना चाहिए।

आज आवश्यकता इस बात की है कि हिमालयी क्षेत्र में होने वाले विकास कार्यों का एक वैज्ञानिक ऑडिट किया जाए। प्रत्येक सड़क, सुरंग, बांध या होटल परियोजना से पहले उसका भूगर्भीय, पारिस्थितिकीय और जलवायु प्रभाव का आकलन अनिवार्य हो। स्थायी विकास केवल तभी संभव है जब उसमें प्राकृतिक पारिस्थितिकी के साथ तालमेल हो।

हिमालय की चुनौतियों का उत्तर केवल निर्माण नहीं है बल्कि पुनर्चिंतन है। हमें न केवल यह तय करना है कि कहां निर्माण होना चाहिए, बल्कि यह भी तय करना है कि कहां नहीं होना चाहिए। हमें विज्ञान की बात सुननी होगी, पारंपरिक ज्ञान को महत्व देना होगा, और हिमालय को एक जैविक इकाई मानकर उसकी सीमाओं का सम्मान करना होगा। तभी धराली जैसी घटनाओं को दोहरने से रोका जा सकता है वरना यदि हमने सबक नहीं लिया, तो अगला विनाश हमारी दहलीज पर दस्तक देने में देर नहीं करेगा।

मंत्रिमंडल विस्तार, निगमों की नियुक्ति दिल्ली में नहीं, बल्कि ओडिशा में ही होगी : मनमोहन सामल

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वर : प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल ने दिल्ली दौरे से लौटने के बाद मीडिया को बड़ा बयान दिया है। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार, निगमों, बोर्डों और समितियों की नियुक्ति को लेकर बड़ी प्रतिक्रिया हुई है। उन्होंने कहा कि सूची दिल्ली में नहीं, बल्कि ओडिशा में ही तैयार की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि निगमों, बोर्डों और समितियों का गठन अगले 15 या 20 तारीख के बाद हो सकता है, लेकिन अभी तक निश्चित तारीख की घोषणा नहीं की गई है।मनमोहन सामल ने बताया कि उन्होंने दिल्ली में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी, केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की है। उन्होंने कहा, स्पार्टी नेताओं के साथ विचार-विमर्श के बाद कोई निर्णय लिया जाएगा।स उन्होंने यह भी बताया कि दिल्ली में संगठनात्मक कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई।

इससे पहले, राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की भी चर्चा हुई थी, लेकिन अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि इस मामले पर दिल्ली में कोई चर्चा नहीं हुई। हालाँकि, निगम-मंडलों में नियुक्तियों को लेकर राज्य में सरगर्मी बढ़ गई है। जहाँ कई नेता इन पदों के लिए इच्छुक हैं, वहीं चर्चा यह भी है कि संगठन में जगह न पाने वाले नेताओं को निगम-मंडलों में जगह दी जा सकती है।

ओडिशा महिलाओं के लिए असुरक्षित; सरकार कुंभकर्णी नींद में

पुलिस थक जाएगी, कांग्रेस नहीं थकेगीः भक्त

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

कटक/भुवनेश्वर : ओडिशा दिन-ब-दिन असुरक्षित होता जा रहा है। महिलाओं और छात्राओं का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आए दिन महिलाओं के उत्पीड़न की खबरें आ रही हैं। लेकिन सरकार और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बलंगा घटना के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार और पुलिस प्रशासन को सचेत करने के लिए आज ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमेटी (ओपीसी) ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास के नेतृत्व में कटक पुलिस महानिदेशक कार्यालय के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया।

यह विरोध प्रदर्शन माता मठ चैक से शुरू होकर महानिदेशक कार्यालय पहुँचा और महानिदेशक कार्यालय के सामने आयोजित किया गया।

इस विरोध प्रदर्शन में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास ने अपने भाषण में कहा कि सरकार पीड़ितों को न्याय दिलाने के बजाय घटना पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। अगर सरकार में महिलाओं और छात्राओं के प्रति थोड़ी भी संवेदनशीलता है, तो ठोस कदम उठाकर मिसाल कायम करे। राज्य में महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और न्याय मिलने तक कांग्रेस अपना संघर्ष जारी

रखेगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में भुवनेश्वर में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस ने अपनी ताकत दिखाई है। बालासोर छात्रा आत्महत्या मामले को लेकर हम राज्य बंद, विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास पर धरना देकर सरकार पर दबाव बना रहे हैं। कांग्रेस राज्य में महिलाओं के न्याय के लिए सड़कों पर उतरी है। आने वाले दिनों में उग्र लेकिन शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। पुलिस थक जाएगी, लेकिन कांग्रेस नहीं थकेगी। कांग्रेस हर थाने के सामने अपने विचार रखेगी, ऐसा अध्यक्ष श्री दास ने कहा।

इस शांतिपूर्ण संकल्पना में पीसीसी अध्यक्ष भक्त चरण दास के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीकांत जेना, पूर्व पीसीसी अध्यक्ष निरंजन पटनायक, शरत पटनायक, जयदेव जेना, पूर्व विधायक मोहम्मद मोकिम, सुरेश कुमार राउतराय, देबाशीष पटनायक, जगन्नाथ पटनायक, रवि मल्लिक, पूर्व सांसद अनंत चरण सेठी, रामचंद्र खुंटिया, विधायक सोफिया फिरदोश, विधायक अशोक दाश, ओडिशा महिला कांग्रेस नेता मीनाक्षी बहिनीपति, उपाध्यक्ष सस्मिता बेहरा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता शिवानंद रॉय, मानस चौधरी, सुरेश महापात्रा, कटक जिला समन्वयक प्रदीप कुमार दास, भुवनेश्वर समन्वयक विश्वजीत दाश, सेवादल अध्यक्ष शुभेंदु मोहंती, मीडिया सेल अध्यक्ष अरविंद दास विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और राज्य पुलिस की निष्क्रियता के कारण राज्य में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बढ़ते मामलों की कड़ी निंदा की और पुलिस को अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करने की सलाह दी।

इस अवसर पर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के निर्देश पर, 11 सदस्यीय प्रदेश महिला प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी की अनुपस्थिति में अतिरिक्त डीजीपी को ज्ञापन सौंपा और महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मीनाक्षी बहिनीपति, विधायक सोफिया फिरदोश, उपाध्यक्ष सस्मिता बेहरा, गिरिबाला बेहरा, मधुस्मिता सेठी, बंदिता परिदा, स्वर्णप्रभा पश्यात, सुनीता बिस्वाल, सस्मिता पांडा, प्रणति मिश्रा, अमृता दास शामिल थीं।

आज के कार्यक्रम का संचालन पूर्व पीसीसी महासचिव विश्वजीत दाश ने किया, जिसमें रजनी मोहंती, प्रकाश मिश्रा, अशोक स्वैन, नलिनी कांत नायक, सिद्धार्थ पूर्वो दास, देबेंद्र साहू, संतोष भोला, निकुंज पशायत, आर्यबीर लेंका, राजीव पटनायक, निरंजन नायक, देबा प्रसाद नायक, तरूण दाश, चिन्मय सुंदर दाश, मनोज राउत, बिप्लब चौधरी, नटवर बारिक, मानस मल्लिक, सोनाली साहू, मनीषा दास पटनायक, जयश्री पात्रा शामिल थे। मधुस्मिता आचार्य, श्रिया स्मिता पांडा, शिल्पीश्री हरिचंदन, अमिता बिस्वाल, प्रमुख युवाओं, महिलाओं, छात्रों और पीसीसी के सभी प्रमुख संगठनों के नेताओं सहित सभी विभागों और प्रकोष्ठों के नेताओं ने मीडिया समन्वयक दीपक कुमार महापात्रा को यह जानकारी दी।

झारखंड के मुरी स्टेशन में ट्रेन पर 18 किलो मादक पदार्थ बरामद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन 'नारकोस' के तहत बड़ी सफलता हासिल करते हुए ट्रेन संख्या 13351 (धनबाद-अलप्पुझा एक्सप्रेस) में 18.3 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मादक पदार्थ की यह बरामदगी मुरी स्टेशन पर की गई है ।

आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर मुरी और सुइसा पोस्ट के चार जवान एएसआई लड्डूरा सवाईयां, कॉन्स्टेबल सत्यानंद कुमार, कॉन्स्टेबल यशवंत कुमार मौर्य सात अगस्त को ट्रेन में एस्कॉर्ट ड्यूटी पर थे। इस क्रम मुरी स्टेशन पर ट्रेन के रुकने के बाद, कोच संख्या एस-3 में दो लावारिस पिट्ठू बैग संदिग्ध रूप से पड़े मिले। जवानों ने तत्काल यात्रियों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी बैग पर स्वामित्व नहीं जताया। संदेह के आधार पर की गई जांच में दोनों बैगों से भूरे प्लास्टिक में लिपटे दो पैकेट मिले, जिनमें गांजा होने की आशंका जताई गई।

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरी पोस्ट के पोस्ट कमांडर निरीक्षक संजीव कुमार मौके पर पहुंचे और आरपीएफ रांची के एएससी अशोक कुमार सिंह को भी सूचना दी गई। अशोक कुमार सिंह की निगरानी में गवाहों की उपस्थिति में बैग खोले गए और बरामद गांजा को मुरी पार्सल कार्यालय में तौला गया, जिसका वजन 18.3 किलोग्राम पाया गया।

शिबू सोरेन के निधन के कारण झारखंड में आदिवासी दिवस काफी सादगी में मना

झारखंड के पूर्व सी एम चंपाई ने जामताड़ा तो मौजूदा सी एम हेमंत ने पैतृक गांव नेमरा से दिया संवाद

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. जामताड़ा में भी ऐसे कई कार्यक्रम आयोजित किये गये. नाला में आदिवासी समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम सह भाजपा विधायक चंपई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां उन्होंने विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासियों के लिए एक और आंदोलन की जरूरत बताया कहा कि आदिवासी को कुछ मिला नहीं खोया है.

जामताड़ा में विभिन्न आदिवासी समाज संगठन द्वारा विश्व आदिवासी दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं. जहां आदिवासी संगठन और समाज के लोग काफी संख्या में भाग लेते हैं. लेकिन इस बार कई जगह पर झामुमो सुप्रीमो दिवंगत शिबू सोरेन के निधन को लेकर आदिवासी संगठनों के द्वारा सादगी से विश्व दिवस मनाया गया. आदिवासी दिवस पर नाला में आदिवासी संगठन समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हेलिकॉप्टर से जामताड़ा पहुंचे. जहां पार्टी कार्यकर्ता और संगठन के लोगों द्वारा उनका स्वागत किया गया.

विश्व आदिवासी के मौके पर पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने कहा कि झारखंड में आदिवासी समाज का एक लंबा इतिहास रहा है. झारखंड में तिलकामांझी से

लेकर अब तक कई महापुरुषों द्वारा आंदोलन किए गए. उन्होंने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस पर आदिवासी समाज कितना पाया खोया इसको लेकर चर्चा करेंगे. उन्होंने कहा कि अब तक आदिवासी समाज को कुछ मिला नहीं खोया है. इसके लिए एक और आंदोलन की जरूरत है.

उधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो इन दिनों पितृ वियोग के कारण अपने गांव में है उन्होंने आदिवासी दिवस पर कहा कि आज विश्व आदिवासी दिवस है। पर मेरे मार्गदर्शक, मेरे गुरु और मेरे बाबा अब सशरीर हमारे साथ नहीं हैं। मगर उनका संघर्ष, विचार और आदर्श हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। वह न केवल मेरे पिता थे बल्कि समस्त आदिवासी समाज, झारखंड की आत्मा, संघर्ष के प्रतीक और जल, जंगल, जमीन के मुखर रक्षक

सीएम ने कहा कि आदिवासी समाज ने मानव जाति को प्रकृति के साथ सामंजस्य में जीवन जीने का मार्ग दिखाया है। उनका जीवन दर्शन प्रकृति से शुरू होकर प्रकृति पर ही समाप्त होता है, लेकिन सदियों से यह समाज शोषित और वंचित रहा है। बाबा ने इस स्थिति को बदलने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया।

उन्होंने बताया कि विश्व आदिवासी दिवस का कार्यक्रम बाबा को हमेशा प्रिय रहा, क्योंकि यह अवसर आदिवासी समाज की समृद्धि, सभ्यता और संस्कृति को एक सूत्र में पिरोने और उनकी प्रतिभा को वैश्विक मंच देने का माध्यम रहा है। सीएम ने वीर पुरखों को नमन करते हुए संकल्प लिया कि उनके दिखाए रास्ते पर चलते हुए झारखंड और देश में आदिवासी अस्मिता की मशाल को और ऊंचा करेंगे।

भारत में भुजारिया त्योहार

त्योहार नहीं, बल्कि समाज में आपसी प्यार और तहज़ीब की खूबसूरत मिसाल है।

भारत में भुजारिया त्योहार एक रिवायती और क़दीम त्योहार है, जो खुसूसन मध्य प्रदेश, और उत्तर भारत के कुछ इलाक़ों में बड़े शौक़ और जोश के साथ मनाया जाता है।ये त्योहार ख़ास तौर पर रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है।इसका ताल्लुक़ ख़ुशहाली, बारिश, नई फ़सल और भाईचारे से है।इस त्योहार का मक़सद बारिश की दुआ मांगना, फ़सल की बरकत और आपसी मिलन को बढ़ाना होता है।त्योहार की रस्में,त्योहार की तैयारी रक्षाबंधन से एक हफ़्ता पहले शुरू होती है। घरों में मिट्टी के छोटे बर्तन या बांस की टोकरी में गेहूं या जौ के दाने बोए जाते हैं, जिन्हें स्भुजारियास कहा जाता है।ये बीज तकरीबन एक हफ़्ते में अंकुरित हो जाते हैं।रक्षाबंधन के बाद महिलाएं और बच्चियां इन भुजारीयों को सर पर रखकर, नग़मे गाते हुए नहर, तालाब या कुएं की तरफ जुलूस में जाती हैं और वहां इनका विसर्जन करती हैं।

इस मौके पर मेलजोल के गीत गाये जाते हैं, एक-दूसरे को भुजारिया पेश किया जाता है और बड़ों से दुआ सलाम लिया जाता है।

भुजारिया त्योहार की जड़ें आल्हा-ऊदल जैसे बहादुर बुंदेलखंडी किरदारों से जुड़ी मानी जाती हैं।समाज में ये त्योहार रूठों को मनाने, नए दोस्त बनाने और मेल-जोल बढ़ाने का जरिया है।बच्चों, औरतों और बुज़ुर्गों में ख़ास जोश पाया जाता है, इलाके के खेल, कुश्ती, मेला और मौसीकी की महफ़िलें इसका हिस्सा होती हैं।भुजारिया की रस्में और रिवायतें सदियों पुरानी हैं और तमाम लोक कहानियों व ज़िन्दगी का अहम हिस्सा बन चुकी हैं। ये सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि समाज में आपसी प्यार और तहज़ीब की खूबसूरत मिसाल है।

डॉ. मुश्ताक अहमद
शाह हरदा मध्य प्रदेश

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023